RAJHIN/2016/70516

Bhilwara/171/2026-2028

सच्चाई से रुबरु

smarthalchal.com

स्मार्ट हलचल

वर्ष-11 | अंक-09 | जयपुर, गुरुवार, 09 जुलाई 2026 | मूल्य-4 रुपये

केन्द्रीय मंत्री ने कोटा के लिए की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की घोषणा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे बनेगा विकास का नया आधार

गडकरी बोले-2 साल में दिल्ली से मुंबई 12-घंटे में पहुंचेंगे, जो बोलेंगे वह करके दिखाएंगे, यही हमारी पहचान

पूरे देश में हाइवे और सड़कों का मजबूत नेटवर्क हो रहा तैयार : लोकसभा अध्यक्ष

जयपुर

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास के वाहक होते हैं। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जिन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है, वहां रोजगार, उद्योग, व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। गडकरी बुधवार को कोटा के गोपालपुरा-मंडाना में आयोजित आमसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कोटा और हाड़ौती क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का 75 से 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले दो वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक सड़क मार्ग से करीब 12 घंटे में यात्रा संभव हो जाएगी।

कोटा को मिलेगा बेहतर सड़क संपर्क

नितिन गडकरी ने घोषणा की कि एनएच-52 से मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाईपास करते हुए 8-लेन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत से लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा कोटा को बालापुरा के रास्ते एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर लंबा चार लेन ग्रीनफील्ड संपर्क मार्ग भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर अगले तीन माह में कार्य शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि भवानीमंडी को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

'अटल एक्सप्रेसवे' बनेगा नया विकास मार्ग

सभा में गडकरी ने कोटा से इटावा तक चंबल नदी के समानांतर बनने वाले नए एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस हाईवे का नाम अब 'अटल एक्सप्रेसवे' रखा जाएगा। यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को समर्पित होगी। करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना की डीपीआर तैयार की जा रही है और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इससे हाड़ौती क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। इससे पहले केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सड़क मार्ग से एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए बूंदी के लबान इंटरचेंज पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मार्ग में रूक कर एक्सप्रेसवे के कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित लगाई गई प्रदर्शनी में धान, सेंड स्टॉन एवं राजीविका की स्टॉल्स का अवलोकन किया।

गडकरी बोले- विकसित भारत के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी

गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जहां अच्छी सड़कें और आधुनिक परिवहन नेटवर्क विकसित होते हैं, वहां निवेश बढ़ता है, उद्योग स्थापित होते हैं और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब तक लगभग 80 लाख टन कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा चुका है, जबकि बायो-बिटुमिन जैसी नई तकनीकों को भी अपनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने गडकरी की सराहना की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश में सड़क अवसंरचना विकास का नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और भारतमाला जैसी परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई गति देंगी। मुख्यमंत्री ने मुकुंदरा टनल प्रोजेक्ट को आधुनिक भारतीय इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि यह परियोजना देश की तकनीकी क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि कोटा को एक्सप्रेसवे से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए डीसीएम रोड से उम्मेदगंज तक चार लेन स्पर एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार की जा रही है। साथ ही राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में कोटा जिले के विकास के लिए लगभग 5 हजार करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए हैं।

ओम बिरला बोले— विकास की नई लाइफलाइन

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नितिन गडकरी के प्रयासों से देश में हाईवे और सड़कों का मजबूत नेटवर्क तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे क्षेत्र के विकास की नई लाइफलाइन साबित होगा और इससे लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। इससे पहले नितिन गडकरी ने बूंदी के लबान इंटरचेंज पर पहुंचकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार

जयपुर। एसओजी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों के जरिए फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा-2022 में दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले महेंद्र कुमार (30) निवासी झाब जिला जालौर को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

एसओजी एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि 19 मार्च, 2023 को आयोजित हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती में महेंद्र कुमार ने पहले से गिरफ्तार आरोपित बृजेश कुमार मीणा निवासी महुआ (दौसा) के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी।

जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने सुसाइड किया

जयपुर। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के हेड और सीनियर प्रोफेसर डॉ. नंदलाल डिसानिया (58) ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना बुधवार सुबह जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके के अग्रसेन नगर की है।

डॉ. डिसानिया के दामाद डॉ. सुरेश चौधरी भी एसएमएस हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन हैं। डॉ. डिसानिया का बेटा अविनाश डिसानिया बुधवार सुबह 6 बजे बहन को एयरपोर्ट छोड़ने चला गया था। परिवार के दूसरे सदस्य शादी में गए थे। डॉक्टर घर पर अकेले थे।

ममता ने 3 लोगों को थप्पड़ मारा

टीएमसी की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके, तो नाराज हुईं

कोलकाता

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बुधवार को झस्ष्ट की रैली में हंगामा हो गया। इस दौरान ममता बनर्जी नाराज हो गई। वे अपनी ही पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं थप्पड़ मारते नजर आईं। दरअसल, रैली बारुईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप-मर्डर के विरोध में निकाली जा रही थी। इस दौरान चोर-चोर के नारे लगने लगे और कुछ लोगों ने रैली में शामिल लोगों पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए।

टीएमसी ने आरोप लगाया कि हंगामा भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान मारपीट भी की। ममता ने कहा कि बंगाल में अराजकता फैल गई है। पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है।

दरअसल, बारुईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप-मर्डर का मामला सामने आया था। इसका मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। जबकि फरार आरोपी कबीर मोल्ला भी गिरफ्तार हो गया है। अब तक इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुणे में इमारत ढहीं, 16 लोग दबे, 6 का रेस्क्यू

सूरत में बाढ़, 3400 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा, करोड़ों का नुकसान

भोपाल/जयपुर

देशभर में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक तक कई राज्यों में बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा असर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिला, जहां भारी बारिश के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हो गईं, कई इलाकों में जलभराव हो गया और हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार को भारी बारिश के कारण कचरे का पहाड़ 3 मंजिला इमारत पर गिर गया, जिससे कचरा प्रबंधन की बिल्डिंग ढह गई। हादसे में 16 लोग मलबे में दब गए थे, जिनमें से छह लोगों को निकाल लिया गया है।

मुंबई से बारिश के कारण 9 फ्लाइट डायवर्ट हुई हैं। वहीं दिल्ली के रोहिणी में भी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। पुणे के खंडाला में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई, जबकि उसका साथी अब भी लापता है।

चित्तौड़गढ़ में 50 मिनट में 3 इंच से ज्यादा बारिश

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में बुधवार दोपहर 50 मिनट में 80 एमएम बारिश हुई। अलवर में मूसलाधार बारिश के कारण बाजार में सड़कें डूब गईं। जिला हॉस्पिटल परिसर में पानी भर गया, जिससे मरीजों के परिजनों को आने-जाने में परेशानी हुई। अलवर शहर के पास तूलेड़ा सरकारी स्कूल में पानी घुस गया। भरतपुर जिले के नदबई में सुबह करीब 5 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ। लगातार बारिश से रेलवे स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई।

बंगाल में बच्ची से रेप-मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर

कोलकाता

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर का एक आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान प्रभास मंडल ने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली। इसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें प्रभास को गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बारुईपुर में 12 साल की लड़की 4 जुलाई को लापता हो गई थी। 5 जुलाई को उसका शव एक तालाब से मिला। पोस्टमॉर्टम में रेप की पुष्टि हुई, जिसके बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस ने रेप-मर्डर के आरोप में प्रभास सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया था। दूसरा आरोपी आनंद सरदार है।

पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की, जिसमें चार लोग लड़की को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिए थे।

युद्धविराम के बीच फिर भड़का युद्ध

ईरान-अमेरिका सीजफायर खत्म

ट्रम्प बोले- आज रात बड़ा हमला करेंगे

तेहरान

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को ह्ञ्ञह समिट के दौरान कहा कि अमेरिका आज रात ईरान पर फिर से बड़े हमले कर सकता है। उन्होंने इससे पहले कहा था कि अब वह ईरान से कोई डील नहीं करना

चाहते। ट्रम्प ने कहा, हमने कल रात उन पर बहुत जोरदार हमला किया था और संभव है कि आज रात फिर से हमला करें। ईरान मिडिल ईस्ट में दबाव बनाता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा।

अमेरिका ने मंगलवार देर रात ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह कार्रवाई होर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई।

ईरान ने मंगलवार को होर्मुज में तीन जहाजों को निशाना बनाया था। ईरान ने बताया कि यह हमले इसलिए किए गए क्योंकि होर्मुज से कमर्शियल जहाज उनके बताए रास्तों से नहीं गुजर रहे थे।

अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया।

जम्मू-कश्मीर में लश्कर कमांडर जाकिर अहमद ढेर

जम्मू

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का टॉप कमांडर जाकिर अहमद गनी मारा गया। बुधवार को सुरक्षाबलों ने उसका शव बरामद किया।

आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सेना ने शनिवार शाम चनापोरा इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन के पांचवें दिन जाकिर गनी का शव बरामद हुआ। एक और आंतकी लतीफ भट के छिपे होने की आशंका है।

जाकिर गनी उन 14 आतंकियों की सूची में शामिल था, जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया था। यह संयुक्त ऑपरेशन जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG), सेना की राष्ट्रीय राइफल्स (RR) और CRPF ने मिलकर चलाया।

आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद शनिवार शाम से चनापोरा इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था।

यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है 9वीं सदी में बना मशहूर प्रम्बानन मंदिर

पीएम मोदी ने संरक्षण और जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट की शुरूआत की

भगवान शिव से जुड़ने का सौभाग्य हमेशा मिला: मोदी

जकार्ता

पीएम मोदी बुधवार को इंडोनेशिया के योग्याकार्ता स्थित देश के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ गए। दोनों ने मंदिर के संरक्षण-जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम ने मंदिर में दर्शन भी किए। उन्होंने मंदिर परिसर में अपने संबोधन में कहा- मुझे किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद प्रम्बानन मंदिर के विकास का मौका मिलना मेरा सौभाग्य है।

इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर योग्याकार्ता के पास स्थित प्रम्बानन मंदिर दक्षिण-पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। पहले स्थान पर कंबोडिया का अंगकोर वाट है। प्रम्बानन मंदिर एक हजार साल पुराना है।

2029 में जीर्णोद्धार पूरा होने पर फिर इंडोनेशिया आऊंगा

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रम्बानन दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय विरासत की दूसरी सबसे बड़ी पहचान है। यहां भगवान शिव, मां दुर्गा और भगवान गणेश की प्रतिमाएं हैं और सदियों से पूजा होती आ रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति प्रबोवो ने उनसे 2029 तक मंदिर के जीर्णोद्धार का काम पूरा करने का वादा लिया है और वह भी वादा करते हैं कि जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद दोबारा इंडोनेशिया आकर इसका जश्न मनाएंगे। उन्होंने इंडोनेशिया के लोगों और शासकों का इस सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर रखने के लिए आभार भी जताया। पीएम ने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण-जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा- मेरा सौभाग्य रहा है कि किसी न किसी रूप में मुझे हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा- मेरा जन्म वडनगर में हुआ, जहां हाटकेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। गुजरात में मुझे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विकास की जिम्मेदारी मिली। मेरी राजनीतिक कर्मभूमि काशी है, जहां काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद हमेशा मिला।

पीएम ने आगे कहा- मुझे केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण और उज्जैन के महाकाल मंदिर के विकास से जुड़ने का अवसर भी मिला। अब करीब 1000-1200 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जुड़ा है, उसके जीर्णोद्धार कार्य की शुरुआत से जुड़ना भी मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानता हूं।

यूपी में रिटायर्ड एआरटीओ के घर 13 किमी सोना, 9 किमी चांदी मिली

दीवारों-पैकेटों में छिपाया था 1.62 करोड़ कैश

लखनऊ

यूपी में रिटायर्ड सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) ललित कुमार के लखनऊ स्थित घर पर विजिलेंस ने छापा मारा। करीब 26 घंटे चली छापेमारी में ललित कुमार के लखनऊ आवास से 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और हीरे के आभूषण बरामद किए हैं। जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। तलाशी के दौरान टीम को करीब 1.62 करोड़ रुपए कैश भी मिला, जो उसने पैकेटों में दीवार और

अलग-अलग कमरों में छिपाकर रखे थे। 15 जगहों पर मकान, फ्लैट और खेती की जमीनों के दस्तावेज भी मिले हैं। विजिलेंस ने बरामद संपत्ति की कुल कीमत करीब 35 करोड़ रुपए बताई है।

आरोपी ललित कुमार मूल रूप से रायबरेली में सेंगहो कोठी के रहने वाले हैं। विजिलेंस विभाग के अनुसार, ललित कुमार के खिलाफ 2024 में कानपुर में तैनाती के दौरान करप्शन की शिकायत की गई थी। उस वक्त वह आरटीओ ऑफिस में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) यानी रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल थे।

दरभंगा में बम विस्फोट चंचल नगर में दो युवक गंभीर घायल, क्षेत्र में दहशत

दरभंगा (एजेंसी)। बिहार के दरभंगा जिले के चंचल नगर में मंगलवार को एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मची और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। घायलों की पहचान लक्ष्मी पासवान के पुत्र रामबाबू पासवान और कमलेश पासवान के पुत्र श्रीकांत पासवान के रूप में हुई है। लोगों की मदद से उन्हें तत्काल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पतोर थाना सहित कई अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विस्फोट किस परिस्थिति में हुआ और बम वहां कैसे पहुंचा। फिलहाल, पुलिस की ओर से विस्फोट के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रारंभिक जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा। इस घटना के बाद पूरे चंचल नगर इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग विस्फोट की आवाज से सहम गए हैं। पतोर थानाध्यक्ष ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

फोरलेन के बीच आया सालों पुराना पेड़, लोगों ने किया विरोध तो डिजाइन बदला

अमृतसर (एजेंसी)। शहर के मेहता रोड फोरलेन निर्माण के दौरान पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी मिसाल कायम की गई है। यहां गिल गांव के पास हाईवे निर्माण में आ रहे करीब 300 साल पुराने पीपल के पेड़ को काटने की योजना थी लेकिन गांव वाले गुरजंट सिंह, सुखबीर सिंह, डॉ. गुरमीत सिंह जोहल समेत अन्य ने इसका विरोध किया, जिसके बाद एनएचएआई ने सड़क का डिजाइन बदल दिया। पेड़ के आसपास की जगह को भी संरक्षित कर दिया। वहीं डीएफओ ने बताया कि यह पीपल का पेड़ करीब 300 साल पुराना है जो बेहद सुंदर और घनी छाया देता है। उन्होंने खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया और इसे संरक्षित रखने के फैसले की सराहना की। यह उदाहरण दिखाता है कि विकास कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी संभव है, बशर्ते सब मिलकर कोशिश करें।

दर्दनाक हादसा : कुएं में गिरे 13 हिरण और एक कुत्ता, सभी की मौत

भोपाल (एजेंसी)। शुजालपुर अनुभाग की कालापीपल तहसील के खरदौनकलां गांव में हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक खेत के कुएं से तेरह हिरणों और एक आवारा कुत्ते के शव बरामद हुए हैं। खेत मालिक कृष्णाबाई पाटीदार के परिजनों को कुएं से तेज दुर्गंध आने पर यह भयावह दृश्य दिखा। शव बुरी तरह सड़े-गले होने के कारण आशंका है कि यह घटना कुछ दिन पहले हुई होगी। सूचना मिलने पर वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होने के कारण नायब तहसीलदार की देखरेख में सभी शवों को कुएं से बाहर निकाला गया। पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद घटनास्थल के पास ही विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि हिरणों का झुंड किसी आवारा कुत्ते से बचने के दौरान तेजी से भागा और कुएं में जा गिरा। जिस कुत्ते से वे बच रहे थे, वह भी शायद उनके साथ ही कुएं में गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि कुएं की मुंडेर (सुरक्षा दीवार) का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त था, संभवतः उसी टूटे हिस्से से ये हिरण गिरे। मृत हिरणों में चार नर और नौ मादा शामिल हैं। कालापीपल-शुजालपुर क्षेत्र हिरणों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। कुछ समय पहले ही यहां से बोमा पद्धति द्वारा सैकड़ों हिरणों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था। यह घटना क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा और कुओं की उचित मुंडेर जैसे सुरक्षा उपायों के महत्व को रेखांकित करती है। वन विभाग ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

पत्नी ने पहले छत से दिया धक्का, बच गया तो ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर कर दिया इंजेक्ट

-पुलिस को किया गुमराह, पोस्टमार्टम में खुला राज, महिला, प्रेमी व दोस्त गिरफ्तार

निजामाबाद (एजेंसी)। तेलंगाना में एक नर्स ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक महिला नर्स ने 30 जून को पति को छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की थी। जब वह बच गया तो अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी नस में लगी ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर इंजेक्ट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नर्स संध्या (32), उसके प्रेमी अनिल और उसके दोस्त वेंकट साई को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह हत्या पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी, जिसकी वजह संध्या का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। यह पूरी घटना निजामाबाद जिले के मोपाल मंडल के न्यालाकल गांव की है। इसकी जानकारी सोमवार को सामने आई। पुलिस के मुताबिक महिला का पति प्रशांत हाल ही में खाड़ी देश से लौटा था। वह किस देश में था, यह जानकारी नहीं मिल सकी है। वापस आने पर उसे संध्या के अफेयर के बारे में पता चला तो उनमें विवाद होने लगे। 30 जून को तीनों आरोपियों ने प्रशांत को पहले शराब पिलाई। फिर मारपीट कर घर की छत से नीचे धक्का दे दिया। हालांकि गंभीर चोटों के बावजूद प्रशांत की जान बच गई। आरोपियों ने उन्हें यह कहकर अस्पताल पहुंचाया कि वह नशे की हालत में वह छत से गिर गए थे। जांच में सामने आया कि संध्या एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में काम कर चुकी है। पुलिस का दावा है कि उसने अपने मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए इलाज के दौरान पति की ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर और एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर दिया था। प्रशांत की मौत के बाद उनकी मां को घटना पर शक हुआ। उन्होंने 1 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें साजिश का खुलासा हुआ। राज तब खुला जब शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। पुलिस की पूछताछ में संध्या ने सच कबूल कर लिया। पुलिस ने पत्नी संध्या और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में वेंकट साई ने भी पहली हत्या की कोशिश में अपनी भूमिका स्वीकार की है।

करूर हादसे में पीड़ितों को मुआवजा देने से रोकने की डीएमके की याचिका खारिज

हम सीएम के काम तय नहीं करेंगे, कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का मंच न बनाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु के करूर में रैली में हुए हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। डीएमके ने मौजूदा टीवीके सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। सीएम विजय हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें मुआवजा और नौकरी देने की बात कही है, डीएमके का कहना था कि सीएम विजय को रोकना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की याचिका को खारिज कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी सीएम की गतिविधियों को तय नहीं करेंगे। जजों ने डीएमके के वकील से कहा कि वह कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का मंच न बनाएं। अगर सत्ताधारी टीवीके के नेता हादसे को लेकर बयान दे रहे हैं, तो डीएमके भी उसके जवाब में बयान दे

सकती है। यह लड़ाई कोर्ट के बाहर लड़ी जानी चाहिए। डीएमके ने याचिका दाखिल कर कहा था कि पिछले साल टीवीके की रैली में हुए हादसे की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सीएम विजय 41 लोगों की मौत वाले इस हादसे के पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने के लिए करूर जाने वाले हैं। डीएमके ने इसका विरोध किया था।

बता दें पिछले साल सितंबर में टीवीके की करूर में एक रैली की थी, जिसमें भगदड़ मच गई थी। इस दौरान 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना की जांच मद्रास हाईकोर्ट ने विशेष जांच दल को सौंपी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई के हाथों में दे दी थी। खास बात यह है कि जांच की निगरानी कोर्ट एक कमेटी भी कर रही है। सीएम विजय पीड़ित परिवारों से मिलने वाले हैं।

छत्तीसगढ़ में गैर मुस्लिम से निकाह करने लेनी होगी वक्फ बोर्ड से अनुमति

-अंतर-धार्मिक निकाह प्रक्रिया को पारदर्शी व व्यवस्थित बनाने नई व्यवस्था लागू

रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में अंतर-धार्मिक निकाह की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। प्रस्तावित नियम अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होंगे। इसके तहत यदि कोई मुस्लिम युवती या युवक किसी गैर-मुस्लिम से निकाह करना चाहता है, तो पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना जरुरी होगा। अनुमति के लिए दोनों पक्षों की सहमति, पहचान संबंधी दस्तावेज, आवश्यक होने पर मतांतरण से जुड़े दस्तावेज और अन्य कानूनी औपचारिकताओं की जांच की जाएगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही निकाह की अनुमति दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के सभी निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं का पंजीयन भी अनिवार्य करने का फैसला लिया है। केवल पंजीकृत मौलाना ही निकाह पढ़ा सकेंगे। बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन कर निकाह कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने बताया कि वर्तमान में कई स्थानों पर निकाह का कोई केंद्रीय रिकॉर्ड नहीं होने से भविष्य में पहचान, वैवाहिक स्थिति और दस्तावेज से जुड़े विवाद सामने आते हैं। नई व्यवस्था के तहत हर निकाह का रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा और एक समान प्रारूप में निकाहनामा और प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि यह व्यवस्था किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि निकाह प्रक्रिया को कानूनी रूप से पारदर्शी बनाने, फर्जी दस्तावेज, विवादित निकाह और शिकायतों की निगरानी के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

कांग्रेस बाद में रोना मतः ओवैसी ने जताई एनआरसी लागू होने की आशंका

-एसआईआर पर सवाल उठाते हुए बोले- अमित शाह कच्चा काम नहीं करते

नई दिल्ली (एजेंसी)। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आशंका जताई है कि भविष्य में इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को भी आगाह करते हुए कहा कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो बाद में शिकायत करने का कोई लाभ नहीं होगा।

वकीलों की एक बैठक को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिना योजना के कोई कदम नहीं उठाते। उन्होंने कहा, अमित शाह कच्चा काम नहीं करते, वे हर कदम एक तय कार्यक्रम के तहत उठाते हैं। मुझे संदेह है कि आखिरकार सरकार एनआरसी लागू करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि जनसांख्यिकी की जांच के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय आयोग भी इसी दिशा का संकेत हो सकता है, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि उनकी आशंका गलत भी साबित हो सकती है।

ओवैसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाना है। उन्होंने तेलंगाना सरकार से स्थायी निवास प्रमाणपत्र (परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट) जारी करने और इसके लिए स्पष्ट मानक तय करने की मांग की। उनका कहना था कि सरकार को समय रहते रचनात्मक कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि यदि गरीबों के नाम मतदाता सूची से कटते हैं तो बाद में रोने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को समय रहते इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग फिलहाल तेलंगाना सहित 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया चला रहा है। ओवैसी का कहना है कि यदि इस प्रक्रिया में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटते हैं, तो भविष्य में उन्हें नागरिकता संबंधी अन्य प्रक्रियाओं में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, एनआरसी को लेकर विपक्षी दल पहले से ही केंद्र सरकार के रुख का विरोध करते रहे हैं।

देशभर में मानसून का कहर...टैंकर-गाडियां बहा ले गई सुरंग की मिट्टी, कई मलबे में दबे; पहाड़ से गिरे पत्थर और मिट्टी से घर-दुकानें बर्बाद हुईं

वायनाड में लैंडस्लाइड, 4 की मौत, डोडा में बादल फटने से बाढ़

वायनाड/जम्मू/भोपाल (एजेंसी)। मानसून देशभर में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मानसूनी बारिश से कई राज्यों और शहरों में स्थिति चिंताजनक हो गई है। केरलम के वायनाड में मंगलवार सुबह तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। वहीं जम्मू-कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाके में बादल फटने से बाढ़ आ गई। पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरने से घर और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सडक़ों पर कई गाडियां मलबे में दब गईं। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 48 घंटे में करीब 15 इंच (380 मिमी) बारिश दर्ज की गई। वहीं, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 35 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। खजुराहो में सबसे ज्यादा 4.4 इंच बारिश दर्ज की गई। बमीठा में नेशनल हाईवे-39 पर 3 फीट तक पानी भर गया।

वायनाड में हादसा कल्लाडी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ। यहां मलप्पुरम-वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए और बैरिकेड भी बह गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसमें दिख रहा है कि 7 जुलाई को सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर सुरंग से तेज लहर के साथ आया मलबा एक टैंकर को तिनके की तरह बहाकर ले गया। दो लोग इसके मलबे में फंसे। पुलिस, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। मलबा हटाने के लिए छ्रष्टक्क मशीनें लगाई गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, लगातार बारिश के कारण सोमवार से ही सुरंग कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था।

भारत-नेपाल सीमा पर यूक्रेनी महिला गिरफ्तार, बिना वैध दस्तावेज नेपाल जाने की कोशिश नाकाम

पूर्वी चंपारण (एजेंसी)। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरपुर थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम के सहयोग से यूक्रेन की एक महिला नागरिक को गिरफ्तार किया है। महिला पर बिना वैध यात्रा एवं आव्रजन दस्तावेज के भारत में रहने और हरपुर बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से नेपाल जाने का प्रयास करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर रही हैं और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों को सीमा क्षेत्र में एक विदेशी महिला की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर हरपुर थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने सैनिक रोड के समीप विशेष जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान महिला को रोककर उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य यात्रा संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके बाद उसे विधिसम्मत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला हरपुर सीमा के रास्ते भारत से नेपाल में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। अब सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह भारत में कब और किस माध्यम से पहुंची, किन-किन स्थानों पर रही और उसके संपर्क में कौन-कौन लोग थे। इसके अलावा इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं इस मामले के पीछे कोई संगठित गिरोह या मानव तस्करी नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। सीमा सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विदेशी नागरिकों के आवागमन से जुड़े मामलों में आव्रजन नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। बिना वैध दस्तावेज के किसी भी व्यक्ति को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने गिरफ्तार महिला के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस, एसएसबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां संयुक्त रूप से मामले के हर पहलू की जांच कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि जांच पूरी होने के बाद इस मामले से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। यह कार्रवाई भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।

राम मंदिर विवाद: मायावती का विपक्ष को चैलेंज, सबूत दो, वरना ये सिर्फ चुनावी दिखावा है

लखनऊ (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चंदे के कथित गबन की जांच को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि मंदिर के प्रबंधकों की मिलीभगत या लापरवाही के कारण गड़बड़ी हो सकती है। 7 जनवरी, 2026 को X पर एक पोस्ट में, मायावती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत विपक्षी दलों की आलोचना की और चेतावनी दी कि ठोस सबूत के बिना उनके दावों को सच्ची निष्ठा के बजाय राजनीतिक दिखावा माना जाएगा।

उन्होंने लिखा कि यूपी में अयोध्या के श्री राम मंदिर के बाद, अब उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी और गबन का मामला भी काफी चर्चा में है। इन दोनों मशहूर धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट से जुड़े मुख्य प्रबंधकों की भी ठीक से जांच होनी चाहिए; वरना, भविष्य में उनकी जगह नियुक्त होने वाले दूसरे मुख्य प्रबंधक इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। मायावती ने आगे कहा कि क्योंकि आम चर्चा है कि निचले स्तर पर जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, वे या तो मुख्य प्रबंधकों की मिलीभगत से हुई हैं या उनकी लापरवाही के कारण। इसलिए, अब इस मामले की ठीक से जांच करना बहुत ज़रूरी है, और सरकार तथा SIT को इस मामले पर खास ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियां 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले गबन के इस मामले का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रही हैं। पोस्ट में लिखा है कि साथ ही, SP, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के वरिष्ठ नेताओं ने यहां (श्री राम मंदिर में) चढ़ावे की भारी चोरी और गबन के जो दावे किए हैं, उनके बारे में उनसे ठोस सबूत भी मांगे जाने चाहिए, ताकि कोई चोर या गबन करने वाला बच न सके; वरना, इसे सिर्फ़ राजनीतिक दिखावा माना जाएगा–यानी सच्ची श्रद्धा नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों को दरकिनार करके ये पार्टियां अब इस मुद्दे की आड़ में चुनाव लड़ना चाहती हैं–आम चर्चा यही है।

राम मंदिर दान में गबन का विवाद उत्तर प्रदेश के बाहर भी चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार की आलोचना की है और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की शुरुआती जांच में काउंटिंग रूम में सुरक्षा में गंभीर चूक और कुछ कर्मचारियों द्वारा कैश को व्यवस्थित तरीके से छिपाने का मामला सामने आया है। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच देखे गए CCTV फुटेज में कर्मचारियों द्वारा कैश के बंडल छिपाने की लगभग 70 संदिग्ध घटनाएं सामने आईं।

बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को एनआईए कोर्ट ने सुनाई सज़ा

लखनऊ (एजेंसी)। भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले 15 व्यक्तियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने कड़ा दंड सुनाया है। लखनऊ स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इन सभी 15 दोषियों को 5-5 साल की कठोर कैद की सजा दी है। ये सभी दोषी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम बताए जा रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है, उनमें महफूजुर रहमान, अल अमीन अहमद, खोखन सरदार, अलाउद्दीन तारीक, जमील अहमद, हुसैन मोहम्मद फहद, शखावत खान, असीदुल इस्लाम, जैनुल इस्लाम, राजीव हुसैन, मोमिनुर इस्लाम, मेहंदी हसन, शाओन अहमद, मोहम्मद जमील और नूर अमीन शामिल हैं।

ये सभी व्यक्ति बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद पश्चिम बंगाल में छिप कर रह रहे थे। आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) ने अदालत को अपनी जांच में बताया कि एक सुनियोजित साजिश के तहत मिथुन मंडल, विक्रम सिंह, महफूज और समीर मंडल उर्फ टोनी, मोहम्मद जमील सहित कुछ अन्य लोग बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में घुसपैठ करा रहे थे। एटीएस ने खुलासा किया कि यह गिरोह एक संगठित सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा था, जो बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराता था। इतना ही नहीं, यह गिरोह घुसपैठियों के लिए फर्जी भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट तक बनवा रहा था। एटीएस ने अदालत को यह भी जानकारी दी कि कई बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनाए गए थे, और मानव तस्करी के माध्यम से उन्हें भारत से कई अन्य देशों में भी भेजा गया था। यह मामला मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। इस गिरोह के सदस्यों को अक्टूबर 2021 में एटीएस ने देश के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई से भारत में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी से जुड़े आपराधिक सिंडिकेट पर कड़ी चोट पड़ी है। एनआईए कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो भारत की सीमाओं का उल्लंघन करने और अवैध गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश करते हैं। यह फैसला अवैध घुसपैठ के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दर्शाता है और भविष्य में ऐसे प्रयासों को रोकने में मदद करेगा। इस तरह की गतिविधियां न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि राष्ट्रीय संसाधनों पर भी अनावश्यक बोझ डालती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा बनी रहे, इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है।

केजरीवाल ने मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प से मांगा लिखित आश्वासन

-ई20 पेट्रोल से गाडियां होंगी खराब तो कंपनियां करेंगी नुकसान की भरपाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को घोषणा की कि वे सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों को चिट्ठी लिखेंगे और ग्राहकों के लिए लिखित आश्वासन मांगेंगे। दरअसल, वे गाडियों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपयोग करने पर आ रही शिकायतों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांग कर रहे हैं।

केजरीवाल ने कहा कि वे कंपनियों से लिखित रूप में आश्वासन चाहेंगे कि यदि उनकी गाडियों में ई20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) का उपयोग किया जाए तो यदि माइलेज 10 फीसदी से अधिक गिरता है, तो क्या कंपनी ग्राहक को नुकसान की भरपाई करेगी? यदि गाड़ी का कोई भी पार्ट डैमेज होता है, तो कंपनी उसे मुफ्त में रिप्लेस करेगी? उन्होंने मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों का जिक्र किया और आरोप लगाया कि उनकी सार्वजनिक बातें और ओनर मैनुअल में दी गई चेतावनियां (जो अक्सर ई10 तक सीमित सिफारिश करती हैं) एक-दूसरे से मेल नहीं खातीं।

30 करोड़ वाहनों को खतरे में डाल रही सरकार

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिना तैयारी के पूरे देश पर ई20 पेट्रोल थोप रही है, जिससे 30 करोड़ वाहन प्रभावित हो सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि कई ऑटो कंपनियों के ओनर मैनुअल में ई10 से अधिक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि कंपनियां सरकार के दबाव में अलग बयान दे रही हैं। उन्होंने मांग की कि पेट्रोल पंपों पर ई0, ई10 और ई20 तीनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएं, जिससे उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार पेट्रोल चुन सकें।

सरकार जबरदस्ती ई20 पेट्रोल थोप रही है

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशभर में ई20 पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंताएं हैं, लेकिन केंद्र सरकार लगातार इसे लागू करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को समझाने के लिए नए-नए तरीके अपना रही है और ऑटो कंपनियों से भी ई20 के पक्ष में बयान दिलवा रही है। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई को छह प्रमुख ऑटो कंपनियों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, जहां ई20 पेट्रोल को सुरक्षित बताया गया।

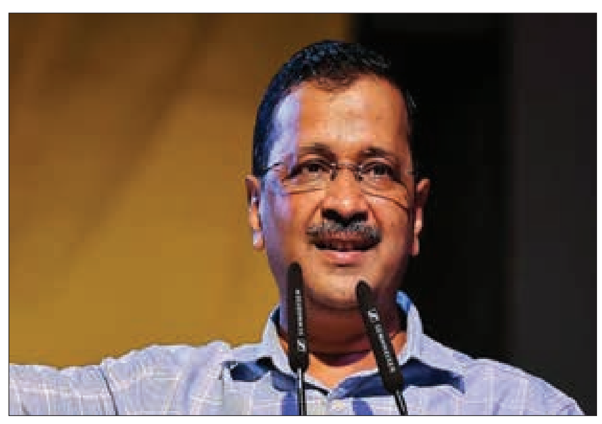

अधूरे निर्माण के विरोध में सड़कों पर उतरे सर्राफा कारोबारी, ढाई घंटे बंद रहा भीलवाड़ा का सर्राफा बाजार

पांच महीने 20 दिन बाद भी पूरा नहीं हुआ सड़क निर्माण, धूल और बदहाल मार्ग से कारोबार प्रभावित, एक्सईएन के आश्वासन पर खुला बाजार

धूल, कीचड़ और टूटी सड़क से ग्राहकों की आवाजाही घटी, कारोबार पर पड़ा सीधा असर, व्यापारियों ने निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने की उठाई मांग

स्मार्ट हलचल

भीलवाड़ा। नगर निगम की लेटलतीफी और अधूरे सड़क निर्माण कार्य के विरोध में बुधवार को शहर के सर्राफा बाजार के व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखकर नगर निगम प्रशासन और स्थानीय राजनेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उग्र प्रदर्शन किया। करीब पांच महीने 20 दिन पहले सड़क खोदने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से नाराज व्यापारियों ने सुबह 10 बजे अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। करीब ढाई घंटे तक सर्राफा बाजार पूरी तरह बंद रहा। बाद में नगर निगम के अधिशासी अभियंता पवन नुवाल के मौके पर पहुंचकर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने के आश्वासन के बाद दोपहर करीब 12.30 बजे बाजार फिर से खुल सका। स्थानीय निवासी विनीत शर्मा ने बताया कि नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के बाद सर्राफा बाजार में सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया था। बड़े मंदिर से सांगानेरी गेट तक सड़क का निर्माण तो पूरा कर दिया गया, लेकिन पुराना भीमगंज थाने से अंजुमन स्कूल तक का हिस्सा पिछले कई महीनों से अधूरा पड़ा है। इस कारण व्यापारियों और आमजन को प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बताया कि अधूरी सड़क पर पीसीसी (प्लेन सीमेंट कंक्रीट) का कार्य हुए भी लगभग एक माह बीत चुका है, लेकिन इसके बाद निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है। दिनभर उड़ने वाली धूल से दुकानों में गंदगी फैल रही है और ग्राहकों का बाजार में आना कम हो गया है। इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। बारिश के दौरान कीचड़ और गड्ढों के कारण हालात और भी खराब हो जाते हैं, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भी भारी असुविधा उठानी पड़ रही है। इन्हीं समस्याओं से परेशान होकर सर्राफा व्यापारियों ने सामूहिक रूप से बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। सुबह जिन दुकानदारों ने दुकानें खोली थीं, उन्हें भी अन्य व्यापारियों ने समझाइश देकर प्रतिष्ठान बंद करवाए। देखते ही देखते पूरा सर्राफा बाजार बंद हो गया और क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। बाजार बंद होने की सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिशासी अभियंता पवन नुवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि अधूरी सड़क का शेष निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र शुरू कराया जाएगा तथा निर्धारित समय में पूरा भी कराया जाएगा। अधिकारियों के इस आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपना आंदोलन समाप्त किया और दोपहर करीब 12.30 बजे बाजार पुनः खोल दिया। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि इस बार भी निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ तो वे और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि सर्राफा बाजार शहर का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग खरीदारी के लिए आते हैं। अधूरी सड़क और धूलभरे माहौल के कारण ग्राहकों ने बाजार का रुख कम कर दिया है, जिससे व्यापारियों को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों ने नगर निगम से मांग की कि अधूरे निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर पूरा कर बाजार क्षेत्र को शीघ्र सुगम और सुरक्षित बनाया जाए, ताकि व्यापारिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो सकें।

दुर्लभ मामला: तहनाल में भेड़ ने बिन पैरों के मेमने को दिया जन्म, शरीर पर पैरों के प्राकृतिक निशान तक नहीं

फिर भी स्वस्थ मेमना..

स्मार्ट हलचल

शाहपुरा। क्षेत्र के तहनाल गांव में प्रकृति का एक बेहद दुर्लभ मामला सामने आया है।किसान अम्बालाल गाडरी की भेड़ ने एक ऐसे मेमने को जन्म दिया है।जिसके चारों पैर नहीं हैं।इतना ही नहीं ग्रामीणों ने बताया कि उसके शरीर पर पैरों के प्राकृतिक निशान तक दिखाई नहीं देते। इस अनोखे जन्म की सूचना फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मेमने को देखने पहुंचने लगे।ग्रामीणों के अनुसार नवजात मेमना फिलहाल स्वस्थ है और मां का दूध पी रहा है।ग्रामीणों ओर किसान अम्बालाल गाडरी ने दावा किया है कि पिछले वर्ष भी इसी भेड़ ने इसी प्रकार के जन्मजात विकार वाले मेमने को जन्म दिया था।उस समय मेमना करीब 10 दिन तक जीवित रहा। चारों पैर नहीं होने के कारण वह न तो चल-फिर सकता था और न ही अपने बल पर खड़ा हो पाता था। परिवार के सदस्य उसकी लगातार देखभाल करते थे। उसे हाथ से दूध पिलाया जाता था और जब भेड़ उसके पास बैठती थी, तब वह स्वयं भी दूध पी लेता था। लगातार 10 दिन तक सेवा और देखभाल के बावजूद अंततः उसकी मृत्यु हो गई।ग्रामीण गोवर्धन सिंह राणावत ने बताया कि लगातार दूसरे वर्ष एक ही भेड़ द्वारा इस प्रकार के मेमने का जन्म होने से पूरे गांव में कौतूहल का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इस तरह का मामला नहीं देखा।वही कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे मामले जन्मजात शारीरिक विकृति,आनुवंशिक कारणों या गर्भ में भ्रूण के विकास के दौरान आई असामान्यता के कारण हो सकते हैं। हालांकि इस मामले का वास्तविक कारण पशु चिकित्सकीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

फिलहाल यह दुर्लभ घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।इस घटना को सुनकर लोग आश्चर्य चकित हो गए हैं।ग्रामीणों का कहना है कि इस मेमने के सभी।अंग पूर्ण विकसित है और व्यवस्थित है।ओर किसान का कहना है कि पूर्ण गर्भकाल होने के बाद ही मेमने का जन्म हुआ है और सामान्यतः गर्भ में कम उम्र के बछड़े तथा अपूर्ण विकसित बछड़े के भी पैर होते है चाहे पूर्णरूप से पोषणयुक्त या विकसित नहीं होते लेकिन इस मेमने के बिल्कुल पैर के प्राकृतिक निसान तक नहीं है।जिससे चर्चा का विषय बना हुआ है।

ब्यावर में 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान

450 किलो संदिग्ध मूंगफली तेल सीज, अजमेर लैब भेजे सैंपल

स्मार्ट हलचल

ब्यावर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की महत्वाकांक्षी योजना 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' के तहत ब्यावर जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर कमल राम मीणा के विशेष निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय गहलोत के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा दल ने एक ट्रांसपोर्ट पर छापा मारकर भारी मात्रा में संदिग्ध तेल सीज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा दल ने सिटी पुलिस थाने के जाब्ते के साथ अरोड़ा ट्रांसपोर्ट पर दबिश दी। यहाँ न्यू पाली स्वास्तिक फर्म द्वारा बिजयनगर भिजवाए जा रहे 'स्वास्तिक मूंगफली तेल' की खेप को रुकवाया गया। टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए तेल के सैंपल लिए और 15-15 किलो के 30 टिन (कुल 450 किलो तेल) को सीज कर दिया। संबंधित दुकानदार को मौके पर पाबंद किया गया है कि लैब रिपोर्ट आने तक वह इस माल की बिक्री नहीं कर सकेगा।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी नारायण सिंह ने बताया कि आगामी शादियों और त्योहारों के सीजन को देखते हुए जिले में यह सघन चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। अगले चरण में तेल निर्माताओं, हलवाई, बेकरी, डेयरी और होटलों की बारीकी से जांच की जाएगी। आज लिए गए सैंपल को जांच के लिए अजमेर लैब भेजा गया है, जहाँ से रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शंभुगढ़ कस्बे में आधार सेवा प्रारंभ

स्मार्ट हलचल|शंभुगढ़

कस्बे में स्थित उपडाकघर में आधार सेवा प्रारंभ हो गई है इससे आधार संबंधी कार्य के लिए अब शंभुगढ़ क्षेत्र की जनता को आसीन्द गुलाबपुरा व अन्य जगह नहीं जाना पड़ेगा ।

आधार कार्ड केंद्र शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है ग्रामीणों द्वारा उपडाकघर के कार्मिको का माला पहनाकर व मुंह मीठा करवा उनका सम्मान किया गया।

शंभुगढ़ में आधार केंद्र सेवा प्रारंभ करने के लिए काफी समय से मांग की जा रही थी।

भजनलाल और गडकरी ने किया एक्सप्रेसवे का निरीक्षण

, बिरला बोले, 'यह देश को जोड़ने वाला विकास का सबसे बड़ा मार्ग'

कार्यक्रम स्थल से तीनों नेता मिनी बस में सवार होकर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने कोटा की ओर हुए रवाना

स्मार्ट हलचल | बूंदी

जिले में बुधवार शाम दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निरीक्षण किया. इस दौरान तीनों नेताओं ने एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य, यातायात सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए इसे देश की प्रगति और आधुनिक आधारभूत संरचना का मजबूत प्रतीक बताया. कार्यक्रम स्थल से तीनों नेता मिनी बस में सवार होकर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने कोटा की ओर रवाना हुए.

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे. यहां प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जनप्रतिनिधियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की. इसके कुछ ही देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला निरीक्षण स्थल पहुंचे. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पहुंचते ही कार्यक्रम का मुख्य चरण शुरू हुआ. लबान इंटरचेंज पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद तीनों नेताओं ने लगभग 10 मिनट तक चर्चा की और एक्सप्रेसवे के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर अधिकारियों से निर्माण कार्य और सुविधाओं की जानकारी ली.

'गडकरी का विजन सड़क निर्माण तक ही सीमित नहीं...': इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कार्यशैली और दूरदर्शी सोच की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने देश को सड़कों के मजबूत नेटवर्क से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है. उन्होंने कहा कि आज भारत की पहचान विश्व स्तर पर आधुनिक सड़क अवसंरचना और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण भी बन रही है. गडकरी का विजन केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार और क्षेत्रीय संतुलन को नई दिशा देने वाला है

यह एक्सप्रेसवे 14 जिलों के लिए विकास की नई जीवनरेखा साबित होगा: बिरला ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे एनएचएआई की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है. यह आठ लेन का आधुनिक एक्सप्रेसवे राजस्थान के 14 जिलों के लिए विकास की नई जीवनरेखा साबित होगा. इसके संचालन से यात्रा का समय कम होगा, परिवहन लागत घटेगी और व्यापार, उद्योग तथा पर्यटन को नई गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि यह एक्सप्रेसवे पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को आपस में जोड़ने वाली देश की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल है. एक्सप्रेसवे के दोनों ओर मजबूत बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया है, जिससे आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगेगी और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी।

भजनलाल शर्मा के आगमन के दौरान स्वागत के लिए खड़े भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा का सुरक्षा के लिए लगाई रेलिंग में कुर्ता फंस कर फट गया. इस दौरान हेलीपेड पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद थे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान हेलीपेड के पास जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन कर संबंधित अधिकारी से जानकारी ली. इस दौरान खनिज विभाग, राजीविका और कृषि विभाग के अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने जानकारी भी ली।

बिजली लाइन निर्माण में लापरवाही का आरोप

खेत में गिरे दो पोल, किसान बोले—बड़ा हादसा होने से पहले सुध ले विभाग

स्मार्ट हलचल|लाडपुरा

लाडपुरा गांव में बागवाले कुएं से खेतों तक बिछाई जा रही नई विद्युत लाइन के निर्माण कार्य में कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। पोलों को पर्याप्त गहराई तक नहीं गाड़ने के कारण दो स्थानों पर बिजली के पोल गिर गए। गनीमत रही कि घटना के समय आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

जानकारी के अनुसार, पोल गिरने से एक किसान की खेत में खड़ी फसल भी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि घटना को करीब पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से अब तक न तो गिरे हुए पोल हटाए गए हैं और न ही निर्माण कार्य में सुधार के लिए कोई कार्रवाई की गई है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बागवाले कुएं से खेत तक लगाए जा रहे अधिकांश पोल केवल दो से तीन फीट गहराई तक ही गाड़े गए हैं, जबकि खेतों में सुरक्षित विद्युत लाइन के लिए पोलों को पर्याप्त गहराई तक स्थापित किया जाना आवश्यक है। ऐसे में भविष्य में पोल गिरने या दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।

किसानों ने बिजली निगम से मांग की है कि सभी पोलों को तकनीकी मानकों के अनुसार कम से कम 7 से 8 फीट गहराई तक मजबूती से स्थापित किया जाए, ताकि किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।

महात्मा गांधी विद्यालय रोपा में 20 में से 9 शिक्षक अनुपस्थित, 6 बिना सूचना गैरहाजिर नोटिस होंगे जारी

स्मार्ट हलचल

जहाजपुर। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा के निर्देश पर एसीबीईओ पुष्कर राज मीणा ने बुधवार सुबह 7:30 बजे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, रोपा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कार्यरत 20 शिक्षकों में से केवल 11 शिक्षक ही उपस्थित मिले, जबकि 9 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए।

जांच में सामने आया कि अनुपस्थित शिक्षकों में से 3 अवकाश अथवा अन्य स्वीकृत कारणों से अनुपस्थित थे, जबकि 6 शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के गैरहाजिर मिले। एसीबीईओ ने बिना सूचना अनुपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

एसीबीईओ पुष्कर राज ने बताया कि निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में विद्यालय स्टाफ की बैठक लेकर सभी कार्मिकों को समय पर विद्यालय पहुंचने और शिक्षण कार्य में लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी गई। भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।वहीं, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोपा के निरीक्षण में सभी शिक्षक एवं कर्मचारी समय पर उपस्थित मिले। विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं।

गुप्तेश्वर वाया गोठ सीसी सड़क निर्माण में महा-घोटाला: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी गुणवत्ता, 6 इंच की जगह महज 3 इंच मिली मोटाई

ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप: सड़क के दोनों किनारों से सुरक्षा दीवार, पुलिया और मिट्टी भराई गायब, पहली ही बारिश में दरकने लगी सड़क, कोर कटिंग जांच की मांग

स्मार्ट हलचल|मांडलगढ़

उपखंड क्षेत्र के गुप्तेश्वर वाया गोठ मार्ग पर करोड़ों रुपये की भारी-भरकम लागत से निर्मित हुई नूतन सीसी सड़क निर्माण कार्य में गंभीर तकनीकी अनियमितताओं, वित्तीय गड़बड़ी और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के सनसनीखेज आरोप सामने आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों और समाजसेवियों ने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभागीय अधिकारियों की साठगांठ पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि निर्माण ठेकेदार ने कागजों में स्वीकृत अनिवार्य कार्यों को धरातल पर पूरा किए बिना ही करोड़ों रुपये का भुगतान उठा लिया है। सड़क की बदहाली को लेकर क्षेत्रवासियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने की मांग की है।

मानकों को ठेंगा: आधी मोटाई में ही समेट दिया करोड़ों का प्रोजेक्ट:

ग्रामीणों ने सड़क की तकनीकी मापदंडों और मोटाई को लेकर सबसे बड़ा खुलासा किया है। सरकारी स्वीकृत मानकों और सार्वजनिक निर्माण विभाग के टेंडर नियमों के अनुसार इस हैवी व्हीकल सीसी सड़क की निर्धारित मोटाई न्यूनतम 6 इंच होनी अनिवार्य थी। लेकिन जब ग्रामीणों ने कई स्थानों पर सड़क के टूटे हुए हिस्सों और किनारों को खुद नापा, तो सड़क की वास्तविक मोटाई महज 3 इंच के आसपास ही पाई गई। मानकों से आधी मोटाई रखना निर्माण गुणवत्ता में एक गंभीर और अक्षम्य अपराध है, जो करोड़ों रुपये की सरकारी राशि के गबन और बंदरबांट की तरफ साफ इशारा करता है।

न मिट्टी भराई हुई और न बनी सुरक्षा दीवार, पहली ही बारिश में कटाव शुरू:

सड़क निर्माण के दौरान तकनीकी नियमों के अनुसार सीसी ब्लॉक को मजबूती प्रदान करने और किनारों को धंसने से बचाने के लिए दोनों ओर मिट्टी भराई की जानी थी, जिसे पूरी तरह छोड़ दिया गया। इसके अलावा, सुरक्षा की दृष्टि से जिन संवेदनशील ढलानों पर रिटेनिंग वॉल (सुरक्षा दीवार) का निर्माण होना था, वह भी गायब है। परिणाम यह हुआ कि सीजन की पहली ही बारिश ने इस भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है और सड़क के किनारे तेजी से कटने लगे हैं। जल निकासी के लिए तय स्थानों पर पाइप और पुलिया नहीं डाले जाने के कारण बरसात का पानी पूरी सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे करोड़ों की यह सड़क समय से पहले ही जमींदोज होने की कगार पर पहुंच गई है।

ग्रामीणों ने दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी, 'कोर कटिंग' जांच पर अड़े:

घटिया निर्माण से नाराज ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से मांग की है कि जिला प्रशासन तुरंत एक स्वतंत्र तकनीकी विंग का गठन करे। सड़क की 'कोर कटिंग' कराकर इसकी वास्तविक मोटाई और सीमेंट-बजरी के अनुपात की वैज्ञानिक जांच की जाए। साथ ही स्वीकृत कार्यों का धरातलीय भौतिक सत्यापन किया जाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही इस महा-घोटाले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो समस्त ग्रामवासी जिला कलेक्ट्रेट और संबंधित विभाग के कार्यालय के बाहर उग्र तालाबंदी और धरना प्रदर्शन के लिए विवश होंगे।

लग्जरी बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान

स्मार्ट हलचल| भीलवाड़ा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रश्मि आर्य ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी यात्री बस में सफर करने से पहले उसकी सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच अवश्य करें। यह सुनिश्चित करें कि बस में इमरजेंसी एग्जिट, दोनों ओर निकास द्वार, अग्निशमन यंत्र तथा इमरजेंसी हैमर जैसी आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध और कार्यशील हों।

उन्होंने कहा कि यदि किसी बस में सुरक्षा मानकों की अनदेखी दिखाई दे तो ऐसी बस में यात्रा करने से बचें और संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें। यात्रियों की थोड़ी-सी जागरूकता किसी बड़े हादसे को रोक सकती है। रश्मि आर्य ने बस संचालकों से भी सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं एसओपी का पूर्ण पालन करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैक्टर व दुपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण पर पेनल्टी में राहत, सितंबर तक एमनेस्टी योजना का लाभ

जिला परिवहन कार्यालय में ट्रैक्टर डीलरों की बैठक आयोजित, वाहन स्वामियों को योजना की जानकारी देने की अपील, जुलाई में विशेष जांच अभियान भी चलेगा

स्मार्ट हलचल

भीलवाड़ा। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2026 के तहत वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई एमनेस्टी योजना-2026 के तहत कृषि ट्रैक्टर एवं दुपहिया वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) के नवीनीकरण पर देय शास्ति (पेनल्टी) में विशेष छूट दी जा रही है। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिक से अधिक पात्र वाहन मालिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में जिला परिवहन कार्यालय, भीलवाड़ा में जिले के ट्रैक्टर डीलरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला परिवहन अधिकारी

रामकृष्ण चौधरी के साथ ही डीलर सुनील बियानी, शांतिलाल गुर्जर, विनोद कोठारी, मुकेश कुमार, राकेश व गजराज उपस्थित रहे। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने एमनेस्टी योजना-2026 की विस्तृत जानकारी देते हुए डीलरों से आग्रह किया कि वे अपने स्तर पर प्रत्येक ट्रैक्टर क्रेता एवं वाहन स्वामी को योजना की जानकारी दें तथा जिन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण लंबित है, उन्हें निर्धारित अवधि में नवीनीकरण करवाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इससे अधिकाधिक वाहन स्वामी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही पेनल्टी छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से भी बच सकेंगे। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दुपहिया वाहनों का समय पर नवीनीकरण नहीं कराने पर 300 रुपये प्रतिमाह तथा कृषि ट्रैक्टरों पर 500 रुपये प्रतिमाह की दर से शास्ति देय होती है। हालांकि एमनेस्टी योजना के तहत इस राशि में विशेष राहत प्रदान की जा रही है। योजना के अनुसार दुपहिया वाहनों पर अधिकतम 1,000 रुपये तथा कृषि ट्रैक्टरों पर एक वर्ष तक लंबित मामलों में अधिकतम 2,500 रुपये और एक वर्ष से अधिक अवधि होने पर अधिकतम 5,000 रुपये तक की शास्ति में छूट का प्रावधान किया गया है।

जुलाई में चलेगा विशेष जांच अभियान

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जुलाई माह में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष और सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान बिना पंजीयन अथवा वैधता समाप्त हो चुके दुपहिया वाहनों तथा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का संचालन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहनों के सभी दस्तावेज अद्यतन रखें और एमनेस्टी योजना का लाभ लेकर लंबित आरसी नवीनीकरण समय पर करवाएं।

अब तक लाखों रुपये की पेनल्टी में मिली राहत

डीटीओ चौधरी ने बताया कि 11 फरवरी 2026 से वर्तमान तक जिले के 88 ट्रैक्टर एवं 231 दुपहिया वाहन स्वामियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। इसके तहत कुल 18 लाख 46 हजार 200 रुपये की पेनल्टी में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी, इसलिए वाहन स्वामी समय रहते इसका लाभ उठाएं।

डीलरों से सहयोग की अपील

बैठक में परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर डीलरों से योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार में सहयोग की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि डीलर अपने ग्राहकों को आरसी नवीनीकरण और एमनेस्टी योजना के लाभों की जानकारी देकर उन्हें समय पर प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक वाहन स्वामी सरकारी राहत योजना का लाभ उठा सकें और विभाग के राजस्व संग्रह में भी वृद्धि हो।

खड़े ट्रेलर में घुसी स्क्रैप भरी पिकअप, परखच्चे उड़े, चालक चमत्कारिक रूप से बचा

स्मार्ट हलचल

गुरला। मंगलवार रात नेशनल हाईवे 758 पर कारोई खुर्द के पास सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में स्क्रैप से भरी तेज रफ्तार पिकअप के घुस जाने से भीषण हादसा हो गया।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह परखच्चे उड़ गए और उसमें भरा स्क्रैप सड़क पर बिखर गया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई।

चालक चमत्कारिक रूप से बचा हादसे में पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन चालक बाल-बाल बच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि चालक को मामूली चोटें ही आई हैं।

स्क्रैप सड़क पर बिखरा, जाम लगा टक्कर के बाद पिकअप में भरा सारा स्क्रैप सड़क पर फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से पिकअप को हटवाया और स्क्रैप को किनारे करवाकर यातायात सुचारू करवाया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिकअप चालक को नींद की झपकी आने या अंधेरे में खड़े ट्रेलर नहीं दिखने के कारण हादसा हुआ।पुलिस ने वाहन चालकों से रात में हाईवे पर सावधानी बरतने और सड़क किनारे वाहन खड़ा न करने की अपील की है।

जन कल्याण ग्रामीण सेवा शिविर में उमड़ी ग्रामीणों की भीड़

विभिन्न विभागों ने किया मौके पर समस्याओं का समाधान

स्मार्ट हलचल | आकोला

पंचायत समिति मांडलगढ़ की ग्राम पंचायत सुरास में आयोजित जन कल्याण ग्रामीण सेवा शिविर-2026 में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक ही स्थान पर सेवाएं उपलब्ध कराईं। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान की गई।

शिविर में राजस्व, पंचायत राज, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जलदाय, विद्युत तथा पशुपालन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने नाम संशोधन,

राजस्व रिकॉर्ड, पेंशन, पट्टा, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े प्रकरण प्रस्तुत किए, जिनका विभागीय अधिकारियों ने प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया।

इस दौरान पात्र लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया तथा ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी देकर उनका अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। शिविर में उपखंड अधिकारी, विधायक प्रतिनिधि मुकेश खंडेलवाल, मांडलगढ़ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्यामलाल अहीर, सरपंच प्रतिनिधि भैरूलाल सालवी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य युवराज सिंह, लोकेश सुथार, कालू सिंह चौहान, नारायण गुर्जर सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

नई पाइप लाइन बनी परेशानी, लीकेज से हजारों लीटर पानी बर्बाद

स्मार्ट हलचल

बिजौलियाँ। कस्बे के वार्ड संख्या 6 में जलदाय विभाग द्वारा करीब 15 दिन पूर्व बिछाई गई नई पेयजल पाइप लाइन अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। पाइप लाइन में कई स्थानों पर लीकेज होने से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। लगातार पानी के रिसाव से मोहल्ले की गलियों में जगह-जगह पानी भर गया है और कीचड़ फैलने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है।

स्थानीय निवासी पंकज मेवाड़ा ने बताया कि जलदाय विभाग ने जल्दबाजी में नई पाइप लाइन तो बिछा दी, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने के कारण पाइप लाइन कई स्थानों से लीकेज हो रही है। लगातार

रिसाव से सड़क पर पानी जमा रहने लगा है, जिससे छोटे-छोटे जलाशय बन गए हैं और आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वार्डवासियों के कहना है कि पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़क को खोदा गया था, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद विभाग ने सड़क की मरम्मत नहीं करवाई। वार्ड 6 और 7 में कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह उखड़ी हुई है तथा गिट्टी फैली होने से दुपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है।

लोगों का कहना है कि पाइप लाइन लीकेज की शिकायत कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक न तो लीकेज की मरम्मत कराई गई है और न ही सड़क को दुरुस्त किया गया है। इससे पानी की बर्बादी के साथ-साथ आमजन की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।

राजस्थान प्रांतीय तैलिक साहू महासभा ने राजकुमार डगवाल को भीलवाड़ा युवा शहर जिलाध्यक्ष किया मनोनीत

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

राजस्थान प्रांतीय तैलिक साहू महासभा, जयपुर ने संगठन के विस्तार और युवा शक्ति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भीलवाड़ा निवासी राजकुमार डगवाल को युवा शहर जिलाध्यक्ष (जिला भीलवाड़ा) पद पर मनोनीत किया है। महासभा के प्रदेशाध्यक्ष देवीलाल साहू द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में यह घोषणा की गई।

नियुक्ति पत्र में उल्लेख किया गया है कि राजकुमार डगवाल की सामाजिक सेवा, कार्यकुशलता, कठोर परिश्रम, निष्ठा, लगन, सक्रियता एवं समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। महासभा ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनके नेतृत्व में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी तथा समाज के युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में संगठन से जोड़ने में सफलता मिलेगी।

महासभा ने नवमनोनीत युवा शहर जिलाध्यक्ष से अपेक्षा जताई

है कि वे संगठन के नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। साथ ही सदस्यता अभियान को गति देते हुए युवाओं, समाजसेवियों एवं मातृशक्ति को संगठन से जोड़ने का कार्य करेंगे तथा समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

राजकुमार डगवाल की नियुक्ति पर समाज के पदाधिकारियों, वरिष्ठजनों एवं युवाओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। समाजजनों ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में भीलवाड़ा में संगठनात्मक गतिविधियों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी तथा समाज के उत्थान के लिए प्रभावी कार्य किए जाएंगे।

प्रदेश महामंत्री पद पर नियुक्त हुए अमित नागौरी, समाज में खुशी की लहर

स्मार्ट हलचल

भीलवाड़ा। अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय संगठन अखिल भारतीय

अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश इकाई दक्षिण-पश्चिम राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश महामंत्री पद पर भीलवाड़ा निवासी एवं सक्रिय समाजसेवी अमित नागौरी की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसन्न मित्तल तथा राष्ट्रीय मंत्री गोपाल गोयल द्वारा उनके लंबे समय से समाज हित में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों, संगठनात्मक अनुभव एवं कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए की गई है। अमित नागौरी पिछले कई वर्षों से अग्रवाल समाज के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक समाज को संगठित करने, युवाओं को जोड़ने तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक कार्यक्रमों के सफल संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी सक्रियता और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उल्लेखनीय है कि यह लगातार तीसरा अवसर है जब भीलवाड़ा जिले के किसी अग्रबंधु को अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश इकाई में प्रदेश महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिली है।

इससे जिले के अग्रवाल समाज का संगठन में बढ़ता प्रभाव भी परिलक्षित होता है। नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री अमित नागौरी ने अपनी नियुक्ति पर राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पद उनके लिए सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे संगठन की राष्ट्रीय योजनाओं एवं उद्देश्यों को प्रदेशभर में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर पूरी निष्ठा एवं समर्पण से कार्य करेंगे। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य नागरिकों, पदाधिकारियों एवं शुभचिंतकों ने अमित नागौरी को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन प्रदेश में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

भाजपा नंदराय मंडल की मासिक बैठक सम्पन्न, बूथ सशक्तिकरण एवं संगठन विस्तार पर जोर

स्मार्ट हलचल | आकोला

भारतीय जनता पार्टी नंदराय मंडल की मासिक बैठक मंडल कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की तैयारियों, सदस्यता अभियान, जनसंपर्क अभियान तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के मुख्य अतिथि एवं मंडल पालक बाबूलाल आचार्य ने कहा कि भाजपा का संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत, अनुशासन और समर्पण से निरंतर मजबूत हुआ है। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से अपने बूथ को सशक्त बनाने तथा सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही नियमित जनसंपर्क बनाए रखने और संगठन के प्रत्येक

कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष प्रकाश सांगावत ने संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि बूथ भाजपा संगठन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और मजबूत बूथ ही मजबूत संगठन की पहचान है।

उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं बूथ अध्यक्षों से संगठन द्वारा सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध एवं प्रभावी निर्वहन करने का आग्रह किया।

बैठक में बूथ समितियों के सुदृढ़ीकरण, नए कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने, सदस्यता अभियान को गति देने तथा जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश पाराशर, मंडल महामंत्री भुवनेश चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष कमलकांत पोरवाल, राजू शर्मा (देवरिया), रामकरण जाट, बूथ अध्यक्ष जय सिंह (गेंदलिया), गोपाल सुवालका (गेहूंली), ईश्वर सोनी, धीरज सेन (नंदराय), रतन बागरिया (किशनगढ़) सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बैठक का समापन राष्ट्रहित, संगठन हित एवं जनसेवा के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने तथा आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाकर अपने घर को रोशन कर बने आत्मनिर्भर

एसबीआई बैंक सरकारी कर्मचारियों के लिए कम समय में करता ऋण उपलब्ध

स्मार्ट हलचल | काछोला

क्षेत्र के धामनिया एसबीआई बैंक शाखा के बैंक कार्मिक सुबहे सिंह मीणा ने धामनिया विद्यालय एसबीआई कैंप में सरकारी कर्मचारियों को आसान किश्तों में ऋण को लेकर चर्चा की।वही बैंक मैनेजर सुबहे सिंह मीणा ने कहा कि

सरकारी कर्मचारी 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत एसबीआई से आसानी से सस्ता सोलर लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाकर आप अपने घर को रोशन कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

एसबीआई के मीणा ने बताया कि एसबीआई बैंक ने बड़ा प्लान बनाया है और लाखों घरों को बिना बिजली के ही रोशन करेंगे,एसबीआई ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना बनाई है।इसके तहत एसबीआई लाखों घरों की छतों पर सोलर ऊर्जा के लिए उपकरण लगाएगा।

यह दस्तावेज आवश्यक - मैनेजर मीणा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीनतम वेतन पर्ची, बिजली का बिल, और केवाईसी दस्तावेज आवश्यक हैं,वही बताया कि मुफ़्त बिजली योजनांतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाये आने वाले वर्षों तक बिजली बिल में बचत एवं ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लाभ उठाए।डिस्बर्सलः एसबीआई द्वारा सब्सिडी की राशि सीधे लोन खाते में जमा होती है।वही सरकारी कर्मचारी पर्सनल लोन,होम लोन,कार लोन सहित आदि आकर्षक व कम ब्याज दर पर ऋण ले सकता है

इस अवसर पर मोहम्मद शाबीर रंगरेज,दुर्गा देवी बलाई,पंकज त्रिवेदी, प्रभात सोनी, संजू बलाई,टीना कुमारी तेली, जनरल अटेंडेंट शंकर लाल, गीता देवी, सीमा देवी सहित आदि उपस्थित थे।

पूर्ण सद्गुरु की शरण से ही निरंकार प्रभु-परमात्मा की प्राप्ति सम्भव-सन्त जसविंदर जी

मांडलगढ़ के त्रिवेणी में बही भक्ति की सरिता,निरंकारी सन्त-समागम में आसपास के गांवों से श्रद्धालुओं ने सत्संग में लिया बढ़चढ़कर भाग

स्मार्ट हलचल | मांडलगढ़

मानव जीवन मे ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है व जीवन को श्रेष्ठ व आनन्दमयी बनाया जा सकता है क्योंकि मानव जीवन को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है । जिने में तो जीवन तो पशु भी विचरण कर रहा है अपना पेट भर रहा है लेकिन सोचने-समझने व विचार करने के साथ ईश्वर को प्राप्त करने की सोच केवल ओर केवल मानव योनि में ही सम्भव है। ये विचार श्री जसमिन्दर सिंह जी मुखी एवं ज्ञान प्रचारक निरंकारी मंडल कोटा जोन की उपस्थिति में त्रिवेणी संगम पर आयोजित सन्त समागम में श्रद्धालुओं के समक्ष व्यक्त किए। सिंह ने अपने विचारों में बताया कि मानव मात्र को उसके कर्मो के

हिसाब से फल मिलता है। परमात्मा की समझ नही होने पर आत्मा चौरासी के चक्कर मे रहती हैं। फिर से ये मानव तन धारण नही करना पड़े व चौरासी के बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है तो केवल सद्गुरु के सहारे यह सम्भव है। अच्छे कर्मो का अच्छा फल व बुरे कर्मो का बुरा फल इंसान को इसी जन्म में भोगना पड़ता है । बुरे कर्मो का फल भोगने के लिए पशु,पेड़ व विभिन्न योनियों को धारण करना पड़ता है। सद्गुरु अच्छे व बुरे कर्मो को तारता है। बुरे कर्म करने वाला लोहे की चेन से बंधा हुआ होता है व अच्छे कर्म करने वाला सोने की चेन से बंधा हुआ होता है लेकिन दोनों प्रकार के लोगो को सद्गुरु ही भव से पार करवा सकता है। किसी भी प्रकार से श्रद्धा से ईश्वर को स्मरण किया जाता है तो वह उस इंसान की समस्याओ को सुनता है व ईश्वर उसकी मदद भी करता है। निरंकार प्रभु परमात्मा को जानकर इससे पाया जा सकता है व मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सच्चे व पूर्ण गुरु की शरण मे जाने से सभी अंधविश्वास से दूरी हो जाती है। सांसारिक सुख तो कभी भी पाए जा सकते है लेकिन निरंकार प्रभु परमात्मा को इन सुखों से पाया नही जा सकता है। निरंकार प्रभु परमात्मा निर्लेप,बेरंगा,अडिग अजर-अमर है। यह निडर है कोई भी शस्त्र इसे काट नही सकता,पानी इसे भिगो नही सकता,अग्नि इसे जला नही सकती है ओर केवल मात्र गुरु की किरपा से ही इसे पाया जा सकता है।ईश्वर हर जगह समाया हुआ है ये कण कण में व्याप्त है। सन्त समागम में क्षत्रिय संचालक सन्त हरिचरण,गणेश महात्मा,ओमप्रकाश मेहरा,,उदय लाल,महात्मा भैरू लाल, मुखी दुर्गालाल,महात्मा पप्पू खटीक, सुखदेव बलाई,मुकेश बैरवा, दुर्गालाल बैरवा,मोहनपुरा सहित अन्य श्रदालु मौजूद रहे। स्थानीय सन्तो द्वारा हिंडौली से आए सन्त सिंह को मांडलगढ़ दुर्ग की तस्वीर,शॉल व दुप्पटा,मालाएं पहनकर स्वागत-सम्मान किया गया। सन्त समागम में श्रद्धालुओं ने गीत,भजन,विचार प्रस्तुत कर सद्गुरु द्वारा बताए जा रहे सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।

भारत विकास परिषद ने जरूरतमंद बेटी को भेंट की सिलाई मशीन

स्मार्ट हलचल | चित्तौड़गढ़

भारत विकास परिषद के सेवा पखवाड़े के तहत चित्तौड़गढ़ स्थित परिषद के स्थायी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पर एक जरूरतमंद बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन भेंट की गई। साथ ही प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली 22 बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। केंद्र की संरक्षिका शशि सनाढ्य ने बताया कि वर्ष 2019 से संचालित यह निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र निरंतर महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है। अब तक 2,723 महिलाएं एवं बालिकाएं यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं, जो आज स्वयं एवं अन्य लोगों के कपड़े सिलकर रोजगार अर्जित कर रही हैं। शाखा प्रमुख सुमन कालिया ने बताया कि वर्तमान में केंद्र पर 22 बालिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। प्रशिक्षिका संगीता जैन द्वारा उन्हें सिलाई का व्यावहारिक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है।सदस्य अल्का जैन एवं अर्चना मोदानी ने बताया कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली 22 बालिकाओं को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

ब्यावर में उमड़ा नारी शक्ति का सैलाब, गूंजा सुरक्षा और सम्मान का संकल्प

वर्धमान कॉलेज में जिला स्तरीय महिला सम्मान एवं संवाद समारोह आयोजित; कलेक्टर, एसपी और एडीजे ने कानून और अधिकारों पर दिया जोर

स्मार्ट हलचल

ब्यावर। राजस्थान पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार पूरे राज्य में 'महिला सुरक्षा संकल्प' (स्ड्डद्धद्वह्ल4 ड्डह्वह्म ष्द्बद्दठ्ठद्बह्ल4 द्धश्वह्-द्द1द्दह्ल4 ड्ड्डश्वद्धड्डठ्ठ) अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को ब्यावर के वर्धमान कॉलेज में जिला स्तरीय महिला वॉलन्टियर्स संवाद एवं महिला सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक रतन सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. अनुकृति उज्जैनिया व वृताधिकारी श्री राजेश कसाना के निकट सुपरविजन में संपन्न हुआ। जिला स्तर के साथ-साथ जिले के सभी थानों पर भी इस अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

अत्याचार के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाएं महिलाएं: जिला कलेक्टर

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कमलराम मीना ने अपने संबोधन में महिलाओं को सशक्त बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, 'महिलाओं को निडर होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा। अपने ऊपर हो रहे किसी भी अत्याचार के खिलाफ बोलना सीखें।' कलेक्टर ने मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि यदि कोई भी पीड़ित महिला शिकायत लेकर आती है, तो उसकी तुरंत सुनवाई कर निवारण किया जाए ताकि उन्हें समय पर न्याय मिल सके।

समानता और अधिकारों से ही बढ़ेगा मान: पुलिस अधीक्षक

ब्यावर पुलिस अधीक्षक रतन सिंह ने समाज में लैंगिक समानता की बात रखते हुए कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने पुरुषों से भी अपील की कि वे हर कार्य में महिलाओं की भागीदारी और उनका सहयोग बढ़ाएं। एसपी ने उपस्थित महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा जारी कानूनी अधिकारों व विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की महत्ता समझाई।

कानूनी रूप से सजग रहें महिलाएं: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सोनल पारीक (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों से रूबरू कराया। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता (फ्री लीगल एड) के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि कानून हर मोड़ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ा है, बस उन्हें बिना डरे आगे आने की जरूरत है।

बेटियों को मिलेगा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

कार्यक्रम की शुरुआत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. अनुकृति उज्जैनिया ने 'महिला सुरक्षा संकल्प' अभियान का परिचय दिया। उन्होंने घोषणा की कि आगामी दिनों में जिले में बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने छात्राओं को इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

इन सुरक्षा तंत्रों और हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी

महिला थानाधिकारी विद्या मीणा ने मंच से राजस्थान सरकार और पुलिस द्वारा संचालित आपातकालीन सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी, ताकि संकट के समय महिलाएं इनका उपयोग कर सकें:

112: इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (आपातकालीन सहायता), 1090: गरिमा हेल्पलाइन, 181: नेशनल वुमन हेल्पलाइन, 1098: नेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930: साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन

अन्य सुरक्षा माध्यम: राजकॉप सिटीजन ऐप, वन स्टॉप सुरक्षा सेंटर और ब्यावर में मुस्तैद 'कालिका पेट्रोलिंग यूनिट'।

इस वृहद संवाद कार्यक्रम में सुरक्षा सखी, महिला सीएलजी सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजीविका, साथिनी, आशा सहयोगिनी, ए.एन.एम./जी.एन.एम., महिला अधिवक्ता, गृहणियां, महिला छात्रावास वार्डन सहित एनएसएस-एनसीसी की छात्राएं, एनजीओ प्रतिनिधि और विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के प्रधानाचार्य व शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।

पत्रकार मुकेश कुमार गुर्जर की सड़क हादसे में मौत

स्मार्ट हलचल

नगर फोर्ट पत्रकार मुकेश कुमार गुर्जर की सड़क दुर्घटना में हुई मौत से न सिर्फ मीडिया जगत बल्कि उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में है। नगर फोर्ट, निवासी मुकेश गुर्जर सोमवार दोपहर एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने अथक प्रयास के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। दर्दनाक पहलू यह है कि मुकेश गुर्जर अपने पीछे दो छोटे भाई और महज 7-8 साल की मासूम बेटी को छोड़ गए हैं। पिता का साया सिर से उठते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में कोहराम मचा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मुकेश कुमार गुर्जर अपनी बेबाक कलम और जनसरोकार की पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। उनके निधन से राजस्थान पत्रिका परिवार सहित प्रदेशभर के पत्रकार स्तब्ध हैं। साथी पत्रकारों ने कहा कि मुकेश हमेशा गरीब, मजलूम की आवाज बनते थे, उनका जाना पत्रकारिता की अपूरणीय क्षति है।

सोशल मीडिया पर भी श्रद्धांजलि का दौर जारी है।मुकेश गुर्जर का अंतिम संस्कार मंगलवार को नगर फोर्ट स्थित पैतृक निवास से किया गया है।

मानसूनी मेहरबानी से बिसुन्दनी बांध में बढ़ी जल आवक

स्मार्ट हलचल

सावर(अजमेर)। जिले में मानसूनी बारिश का असर अब जल स्रोतों पर भी दिखाई देने लगा है। सावर उपखंड की ग्राम पंचायत गोरधा स्थित बिसुन्दनी बांध में लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को बांध में 1 मीटर पानी दर्ज किया गया। सीजन की पहली अच्छी बारिश से बांध में पानी की आवक शुरू होने पर आसपास के किसानों में खुशी का माहौल है।

बिसुन्दनी बांध क्षेत्र के हजारों बीघा कृषि क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी भूमिका निभाता है। बांध में पानी भरने से जहां दो मुख्य नहरों के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, वहीं आसपास के कुओं और भूजल स्तर में भी बढ़ोतरी होती है। बांध की कुल भराव क्षमता 3.27 मीटर है।

कांग्रेस नेता सांवर लाल मीणा ने बताया कि डेम में पानी की आवक से कमांड एरिया सहित छोटे और सीमांत किसान परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा। पहली ही बारिश में जलस्तर बढ़ने से किसानों में खासा उत्साह है और अच्छी फसल की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष बिसुन्दनी बांध पर करीब दो महीने तक चादर चलने से चिकल्या और लोधा का झोपड़ा गांवों का संपर्क बाधित हो गया था। इस समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने गोरधा-चिकल्या तथा चिकल्या-पिपलाज मार्ग पर लगभग 2.25 करोड़ रुपये की लागत से दो बड़ी पुलियों के निर्माण की घोषणा कर बजट स्वीकृत कराया, जिससे भविष्य में बरसात के दौरान ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है।

नाथद्वारा में कैफीनेटेड बेवरेज के भ्रामक प्रचार के खिलाफ हुई कार्यवाही

स्मार्ट हलचल |राजसमन्द

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण डॉ टी शुभमंगला के निर्देशो पर जिले में कैफीनेटेड बेवरेज के भ्रामक प्रचार के खिलाफ कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमंचंद शर्मा एवं जितेन्द्र डांगी के दल ने नाथद्वारा बस स्टेण्ड रोड़ रावतो के दरवाजे के पास महावीर जनरल स्टोर कर कार्यवाही करके रेड बुल तथा हैल ब्रांड के नमुने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत लेकर परिक्षण हेतु जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भिजवायें गये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि उक्त नमुनो में कैफिन की मात्रा पाई जाती है जो गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा कम उम्र के बच्चों के लिये हानिकारक होती है। इसका प्रचार एनर्जी ड्रिंक के रूप में किया जाता है जो मिसलीडिंग की श्रेणी में आता है। फर्म पर कार्यवाही करते हुए 1848 कैन अग्रिम आदेशो तक सीज किये गये है।

उन्होंने बताया कि जिले में मिलावट के विरूद्ध नियमित कार्यवाही की जा रही है, तथा कोई भी व्यक्ति मिलावट की शिकायत कर सकता है।

मानवता फिर शर्मसार: नैनवां में पूर्व सरपंच को अर्धनग्न कर काटे बाल, रेठोदा में भी हो चुकी है मॉब लिंचिंग, पुलिस ने दर्ज किया केस

स्मार्ट हलचल

नगर फोर्ट। थाना क्षेत्र की कचरावता पंचायत के रायपुरा गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में बूंदी जिले के नैनवां क्षेत्र स्थित बामनगांव के पूर्व सरपंच अनिल हरिजन को पकड़कर उसके साथ बर्बरता की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अनिल हरिजन को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद भीड़ ने कानून अपने हाथ में लेते हुए उसे अर्धनग्न कर दिया और उसके बाल काट दिए। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

ग्राम रेठोदा में भी हो चुकी है ऐसी घटना

गौरतलब है कि इससे पहले भी रेठोदा में दिन में ही चोरी करता एक युवक ग्रामीणों ने पकड़कर रस्सियों से बांधा और जमकर पिटाई की थी। क्षेत्र में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं।

थानाधिकारी ने कहा - होगी सख्त कार्रवाई

मामला संज्ञान में आते ही नगर फोर्ट थानाधिकारी बाबूलाल ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है।

थानाधिकारी बाबूलाल ने कहा, 'कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। नियमानुसार इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।पुलिस जांच में जुटी, वीडियो की पुष्टि नहीं

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वायरल हो रहे वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। चोरी का आरोप हो या कोई अन्य अपराध, सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है। कानून हाथ में लेना खुद एक गंभीर अपराध है।

बेहजम का सामुदायिक शौचालय डेढ़ साल से बंद, कागजों में लाखों का रखरखाव, धरातल पर बदहाली

स्मार्ट हलचल| बेहजम खीरी

एक ओर सरकार स्वच्छ भारत मिशन और संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत साफ-सफाई और बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं का दावा कर रही है, वहीं बेहजम ब्लॉक मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत का सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय पिछले करीब डेढ़ वर्ष से बंद पड़ा है। हालत यह है कि शौचालय के मुख्य द्वार पर सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक संचालन का समय लिखा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है।

शौचालय के बाहर गंदगी, कूड़े के ढेर और झाड़ियां जमा हैं। इससे कस्बे में आने वाले राहगीरों, व्यापारियों और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें खुले स्थानों या अस्पताल परिसर के आसपास शौच के लिए जाना पड़ता है, जो स्वच्छता अभियान के दावों पर सवाल खड़े करता है।

मलिकपुर निवासी जाहिद खान ने बताया कि सामुदायिक शौचालय करीब डेढ़ वर्ष से बंद है। वहीं दुकानदार प्रमोद कुमार ने कहा कि उनकी दुकान शौचालय के पास होने के बावजूद सुविधा न मिलने से उन्हें आवश्यकता पड़ने पर करीब दो किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

शौचालय की केयरटेकर रेणु देवी ने बताया कि उन्हें

सरकार से 6,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता है, लेकिन शौचालय के रखरखाव के लिए निर्धारित 3,000 प्रतिमाह की राशि कभी उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका कहना है कि बिना बजट के साफ-सफाई और मरम्मत कराना संभव नहीं है।

वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी दिलीप भार्गव का कहना है कि केयरटेकर द्वारा रखरखाव संबंधी बिल प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए भुगतान नहीं किया गया। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी अभिलेखों में हर माह रखरखाव का खर्च दर्ज किया जाता है, जबकि मौके पर शौचालय बंद और बदहाल पड़ा है।

स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती, 10 वाहन थानों में बंद, 17 के चालान

8 से 15 जुलाई तक पुलिस-परिवहन विभाग का संयुक्त अभियान, वाहनों पर होगी कड़ी कार्रवाई

स्मार्ट हलचल| लखीमपुर खीरी

जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) शांति भूषण पांडेय के नेतृत्व में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 10 वाहनों को संबंधित थानों में निरुद्ध किया गया, जबकि 17 वाहनों का चालान किया गया।

एआरटीओ शांति भूषण पांडेय ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 17 स्कूली वाहनों की जांच की गई। जांच में चार वाहन अनफिट पाए गए, जबकि कई वाहन बिना वैध दस्तावेजों के संचालित होते मिले। इसके अलावा दो अन्य वाहनों को भी नियमों के उल्लंघन के चलते बंद कराया गया। वहीं चार निजी वाहन स्कूल वाहनों के रूप में संचालित पाए जाने पर उन्हें भी संबंधित थानों में निरुद्ध कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की टीम विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर स्कूली वाहनों का भौतिक निरीक्षण कर रही है तथा फिटनेस, परमिट, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच की जा रही है। जिन वाहनों के दस्तावेज अधूरे या समाप्त हो चुके हैं, उनके संचालकों को तत्काल नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

एआरटीओ ने जिले के सभी स्कूल वाहन स्वामियों से अपील की कि जिन वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा या प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, वे तत्काल नवीनीकरण करा लें। अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में निजी अथवा अनफिट वाहनों से स्कूल न भेजें। साथ ही सभी विद्यालय प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों से कहा गया है कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसे किसी भी वाहन का संचालन न होने दें, जिसकी फिटनेस, परमिट, बीमा अथवा प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो चुकी हो।

परिवहन विभाग ने बताया कि 8 जुलाई से 15 जुलाई तक पुलिस एवं परिवहन विभाग का संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा, बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र अथवा अन्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों के विरुद्ध चालान, सीज एवं निरुद्ध करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान स्कूलों के स्वामित्व वाले वाहनों के साथ-साथ निजी वाहनों की भी विशेष जांच होगी, जो नियमों की अनदेखी करते हुए स्कूली बच्चों का परिवहन कर रहे हैं।

उदयपुर के यशुराज जोशी ने रचा इतिहास

भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जूनियर रिसर्च फेलोशिप में हासिल की अखिल भारतीय द्वितीय रैंक

स्मार्ट हलचल|उदयपुर

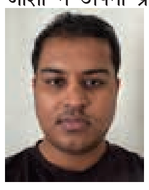

शहर के होनहार युवा यशुराज जोशी ने अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय देते हुए भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) की वर्ष 2026 की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (मात्रात्मक अर्थशास्त्र) प्रवेश प्रक्रिया में अखिल भारतीय स्तर पर द्वितीय रैंक प्राप्त कर उदयपुर और राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। आधिकारिक मेरिट सूची में उनका पंजीकरण क्रमांक जेक्यूई-डीएच-ई052 द्वितीय स्थान पर दर्ज है तथा उन्हें संस्थान की ओर से अनंतिम प्रवेश सीट का प्रस्ताव भी प्रदान किया गया है।

उदयपुर के सृजनधर्मी शिक्षक और प्रस्तर शिल्पकार हेमन्त जोशी के पुत्र यशुराज जोशी ने लिखित परीक्षा और उसके बाद आयोजित साक्षात्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देशभर के प्रतिभागियों के बीच यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। यह परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित एवं प्रतिस्पर्धी शोध प्रवेश परीक्षाओं में गिनी जाती है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शोध करने का अवसर मिलता है।

वर्तमान में नवरत्न कॉम्प्लेक्स, भुवाणा में निवासरत यशुराज की इस सफलता से परिवार, शिक्षकों और शुभचिंतकों में हर्ष का माहौल है। उनकी इस उपलब्धि को शहर के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि येशुराज भविष्य में शोध और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ हासिल कर देश का नाम रोशन करेंगे।

हर सेकंड कीमती है: विश्व पैरामेडिक्स दिवस पर जीडी गोयनका हेल्थकेयर एकेडमी में हुआ शानदार आयोजन

स्मार्ट हलचल

ब्यावर। विश्व पैरामेडिक्स दिवस के अवसर पर ब्यावर के अम्बा बाड़ी स्थित डीपीएस विद्यालय परिसर में संचालित 'जीडी गोयनका हेल्थकेयर एकेडमी' में एक विशेष जागरूकता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन, पैरामेडिकल सेवाओं के महत्व और समाज में पैरामेडिक्स की रीढ़ की हड्डी जैसी भूमिका से परिचित कराना था।

जीवन रक्षक तकनीकों का हुआ प्रदर्शन

कार्यक्रम के दौरान एकेडमी के छात्र-छात्राओं ने प्राथमिक उपचार, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं,

रोगी प्रबंधन और जीवन रक्षक तकनीकों पर आधारित व्यावहारिक और बेहतरीन प्रस्तुतियाँ दीं। विशेषज्ञों ने इस दौरान छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि किसी भी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या मेडिकल इमरजेंसी के समय पैरामेडिक्स ही 'फर्स्ट रेस्पॉन्डर' (सबसे पहले पहुँचने वाले) होते हैं। उनका त्वरित निर्णय और प्रारंभिक उपचार ही मरीज को जीवनदान देता है।

केवल डिग्री नहीं, संवेदनशील प्रोफेशनल बनना जरूरी: सेंटर हेड इस अवसर पर छात्रों को केवल डिग्री हासिल करने के बजाय एक कुशल, संवेदनशील और जिम्मेदार हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनने का संदेश दिया गया। संस्थान के सेंटर हेड पियूष सोनी ने अपने संबोधन में कहा: 'जीडी गोयनका हेल्थकेयर एकेडमी का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम को पूरा कराना नहीं है, बल्कि मेडिकल इंडस्ट्री की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष, आत्मविश्वासी और रोजगारोन्मुख हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स तैयार करना है।'

छात्रों ने ली सेवा और कर्तव्यनिष्ठा की शपथ

कार्यक्रम के समापन पर सभी विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में पूरी लगन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के साथ कार्य करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही, सभी ने समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और आपातकालीन परिस्थितियों में जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने का संकल्प लिया।

इस गरिमामयी समारोह में संस्थान प्रबंधन के सदस्यों सहित फैकल्टी और विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रूचि राजपूत, डॉ. मनोज पोरवाल और हर्षित रांकावत सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

सर्जीकल ग्लब्स फैक्ट्री पर कोर्ट का बड़ा एक्शन, कॉपीराइट उल्लंघन मामले में 2 बड़ी मशीनों को कुर्क कर किया

स्मार्ट हलचल|धौलपुर

रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक नामचीन सर्जीकल ग्लब्स फैक्ट्री पर बड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है। जहां कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करने के मामले में एफ-374 रीको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन स्थित स्वयेर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की सर्जीकल ग्लब्स फैक्ट्री पर गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि जिसके मालिक संजीव गौड़ हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 मई 2026 एवं 22 जून 2026 को जिला न्यायालय धौलपुर को सख्त आदेश दिए थे कि 7 अगस्त 2021 के आदेश को पुनर्जीवित कर फैक्ट्री की दोनों सर्जीकल ग्लब्स मशीनों को कुर्क व सीज किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के उन्हीं आदेशों की अनुपालना में जिला एवं सत्र न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश संजीव मागो ने सर्जीकल ग्लब्स फैक्ट्री स्वयेर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की 2 बड़ी मशीनों को कुर्क कर सील करने के आदेश दिए। इसके बाद कोर्ट के कुर्की वारंट की तामील करते हुए मौके पर पहुंचे न्यायिक अमले ने फैक्ट्री

की दो मुख्य मशीनों को कुर्क कर सील कर दिया है।मिली जानकारी के अनुसार उक्त फैक्ट्री द्वारा मैसर्स अनोन्दिता हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के डिजाइन का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सर्जीकल ग्लब्स तैयार किए जा रहे थे। इसे बौद्धिक संपदा अधिकार का सीधा उल्लंघन मानते हुए पीड़ित पक्ष ने न्यायालय की शरण ली थी। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उक्त फैक्ट्री के खिलाफ कुर्की के कड़े आदेश जारी किए। न्यायालय के आदेश पर नियुक्त कमिश्नर/सेल अमीन की टीम भारी पुलिस बल के साथ जब रीको स्थित ग्लब्स फैक्ट्री पहुँची, तो वहां हड़कंप मच गया। टीम ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उत्पादन कार्य में इस्तेमाल हो रही 2 बड़ी सर्जीकल ग्लब्स मशीनों को अपने कब्जे में लिया, उनकी कुर्की की। साथ ही मशीनों को पूरी तरह चैन डालकर व ताला लगाते हुए कोर्ट की मोहर सील लगाकर सील कर दी हैं। अब इन दोनों मशीनों से किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं किया जा सकेगा। इस दौरान मैसर्स अनोन्दिता हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वकील श्रीकांत श्रीवास्तव, कमल लोधी और अनस खान सहित कंपनी के प्रतिनिधि के चंद्रपाल चौधरी मौके पर मौजूद रहे। रीको इंडस्ट्रियल एरिया में हुई इस कार्रवाई से स्थानीय उद्योगपतियों और व्यवसायियों में खलबली मच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रांड्स की पायरेसी और कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों में कोर्ट अब बेहद सख्त रुख अपना रहा है, जिससे नकली या कॉपी उत्पाद बनाने वालों पर लगाम कसी जा सके। बता दें कि जब कोई संस्थान किसी दूसरे के रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, लोगो, या पेटेंट डिजाइन की हूबहू नकल कर बाजार में माल बेचता है, तो यह कानूनी अपराध है।

क्या आप भी जल्दी जल्दी नौकरी बदलते हैं ? ये हैं फायदे एवं नुकसान

एक तो लोगों को नौकरी मिलना आज के समय में बेहद मुश्किल का कार्य है, वहीं कई लोग भाग्यशाली होते हैं, जिन्हें एक नौकरी छोड़ने से पहले ही दूसरी नौकरी मिल जाए! ऐसे में थोड़ी ग्रोथ के लिए लोगबाग जल्दी-जल्दी नौकरी चेंज करने लगते हैं। शायद आप भी उनमें से हों, किन्तु अगर आप भी जल्दी जल्दी नौकरी चेंज करते हैं तो यह जान लें कि शार्ट टर्म में बेशक इसके कुछ फायदे दिखें, किन्तु दीर्घावधि में इसका काफी नुक्सान होता है।

हालांकि अभी के समय में हालात यह हैं कि अब पहले की तरह लोग एक ही नौकरी पर बहुत दिन तक कार्य नहीं करते हैं, बल्कि नौकरी चेंज करने में वह अपनी ग्रोथ देखते हैं, और उसी अनुरूप डिसीजन भी लेते हैं।

किंतु जॉब बदलने का फैसला कुछ मामलों में बेशक ठीक लगता है, किंतु कुछ मामलों में यह कहीं ना कहीं नुकसान देता है। आइये जानते हैं.अगर फायदे की बात करें तो आप यह जान लीजिए कि जॉब बदलने में सबसे पहले तो कुछ परसेंट ही सही, मगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके काम के अधिक से अधिक पैसे मिलें, और एक नौकरी में अगर उस अनुरूप ग्रोथ नहीं होती है, तो वह जॉब बदलना चाहता है, और ऐसे में उसे तुरंत ही ग्रोथ मिल जाती है।

वहीं अगर दूसरे फायदे की बात करें तो इससे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपका नेटवर्क बेहतर होता है। अगर एक कंपनी में आप जॉब करते हैं, फिर दूसरी कंपनी में जाते हैं, और इस तरीके से अलग-अलग कंपनी में आपका बेस तैयार होता चला जाता है।

इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही कंपनी में काम करने पर आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। आपकी स्किल कहीं ना कहीं सैचुरेट हो जाती है, तो दूसरी कंपनी में जब आप जाते हैं, तो वहां कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलता है। चाहे वहां आपका नया सीनियर हो, चाहे वहां का इनवायरमेंट हो, आप उस कंपनी से नई चीजें जरूर सीखते हैं, और यह वह चीज है जो आपको आने वाले दिनों में मजबूती करती है। इसके अलावा कई भारत लोग एक जगह पर कार्य करने से बोर भी हो जाते हैं, ऐसे में नयी जॉब में उन्हें नयापन भी मिलता है।

हालांकि यह इसका पॉजिटिव पक्ष है, किंतु कुछ निगेटिव पक्ष भी हैं, जिन्हें आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

नुकसान की बात करें तो बार बार जॉब चेंज करने से पोजीशन के मामले में आपके आगे बढ़ने पर असर पड़ सकता है। जी हाँ! एक ही कंपनी में जब आप काम करते हैं, तो वहां आपकी कांस्टेंट ग्रोथ होती है। वहां आपको प्रमोशन मिलता रहता है, किंतु जब आप दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो सीनियर पोजिशन पर आपको पहुंचने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है।

इससे आपकी लॉयल्टी भी चेक की जाती है। अगर आप कुछ ज्यादा ही जॉब चेंज करते हैं, तब आपको किसी हायर पोजिशन पर जॉब देने से एचआर मैनेजर निश्चित ही कई बार सोचेगा।

कंपनी अगर किसी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर आप की हायरिंग कर भी लेती है, तो भी कंपनी श्योर नहीं हो पाती है कि आप आखिर कितने दिन जॉब करेंगे? कहीं आप बीच में ही जॉब छोड़ कर कहीं और तो नहीं चले जाएंगे? ऐसे में आप शक के घेरे में आ जाते हैं!

यह कार्य सिर्फ पोजीशन के मामले में ही नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट अलॉटमेंट के मामले में भी है, तो क्लाइंट इंटरेक्शन के मामले में भी है। जब तक आप किसी कंपनी के लम्बे समय तक वफादार नहीं होते हैं, तब तक किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमांड आपके हाथ में देने से निश्चित रूप से वह कंपनी हिचकिचाएगी। इसी प्रकार से बड़े क्लाइंट हैंडलिंग में भी कंपनी आपको तब तक इंवॉल्व नहीं करेगी, जब तक आप उसके प्रति लॉयल साबित न हो जाएँ! ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी संभावनाओं से आपके दूर रहने की शुरुआत हो जाती है।

कंपनी बार-बार चेंज करने का आपके फाइनेंसियल पोजीशन पर भी खासा असर पड़ता है। चाहे आप क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें, चाहे आप होम लोन या दूसरे लोन के लिए अप्लाई करें.आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर चेक की जाती है। आप किस कंपनी में कितने लंबे समय तक रहे हैं, यह आपके लिए एक प्लस प्वाइंट साबित होता है। वहीं अगर आप बार-बार अपनी जॉब चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप की फाइनेंसियल स्टेबिलिटी पर एक सवाल खड़ा होता है।

मैनेजेरियल स्किल डेवलपमेंट पर पड़ता है फर्क

जी हां! ऊपर से आपको बेशक लगे कि आप कुछ चीजें ऊपर ऊपर समझ गए हैं, किंतु प्रबंधन के गुणों को आप तब तक नहीं समझ सकते, जब तक आप किसी कंपनी में देर तक नहीं टिकेंगे! कहीं टिक कर काम करने के बाद ही कंपनी पॉलिटिक्स, प्रबंधन टेक्निक आप समझ पाते हैं। कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किस प्रकार लेती है, वास्तव में उसकी रुचि और भविष्य की योजनायें क्या हैं, यह आप गहराई से एक समय के बाद ही समझ पाते हैं। अगर बाद में आप कभी अपना उद्यम शुरू करना चाहें, तो इसलिए जरूरी है कि किसी कंपनी में आप देर तक टिक कर काम करें, अन्यथा आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे।

पॉलीमर साइंस में बीटेक करने के बाद है शानदार करियर संभावनाएं

विदेश ही नहीं, भारत में भी कई पॉलिमर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं। नतीजतन, करियर विकल्प के रूप में केमिकल इंजीनियरिंग या पॉलिमर इंजीनियरिंग का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद पॉलीमर साइंस में बीटेक कर सकते हैं।

मौजूदा तकनीकी दौर में पॉलीमर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इनमें प्लास्टिक, मोल्डेड सामग्री, सिंथेटिक फाइबर, रबर आदि शामिल हैं। ईको-फ्रेंडली और रीसाइक्लेबल प्लास्टिक के साथ इन सभी पॉलीमर प्रोडक्ट्स के उचित प्रबंधन की आवश्यकता भी समय के साथ बढ़ रही है। यह काम पॉलिमर इंजीनियर्स करते हैं। वे प्लांट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन और थर्मोडाइनेमिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। विदेश ही नहीं, भारत में भी कई पॉलिमर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं। नतीजतन, करियर विकल्प के रूप में केमिकल इंजीनियरिंग या पॉलिमर इंजीनियरिंग का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद पॉलीमर साइंस में बीटेक कर सकते हैं। आज के इस लेख में हम आपको पॉलीमर साइंस में बीटेक के बाद करियर अवसर के बारे में जानकारी देंगे-

पॉलिमर इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के अवसर

पॉलिमर इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद आप सरकारी फर्मों जैसे सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला और सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि में बतौर जूनियर रिसर्च फेलो काम कर सकते हैं। इन फेलोशिप कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कम से कम 55% अंकों के साथ एम ाटेक डिग्री प्राप्त करने के बाद कोई भी नेट के लिए बैठ सकता है। जिन उम्मीदवारों ने अपनी बी टेक डिग्री में 60% अंक प्राप्त किए हैं, वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैज्ञानिक या इंजीनियर के रूप में 40,000/- रुपये के मासिक वेतन के साथ काम कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी वैज्ञानिक बी पद की भूमिका में पॉलिमर इंजीनियरिंग स्नातकों की भर्ती करता है। इनके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) जैसे संगठन भी पॉलिमर इंजीनियरिंग में बी टेक स्नातकों को नियुक्त करते हैं। इनके अलावा स्नातक डिग्री धारक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑयल इंडिया लेबोरेटरीज, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग प्लांट्स और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन (ओएनजीसी) आदि विभागों में भी रोजगार पा सकते हैं। उम्मीदवार विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में लेक्चरर पद का विकल्प भी चुन सकते हैं।

पॉलिमर इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद निजी क्षेत्र के अवसर

जर्मन आधारित कंपनी विंडमोलर एंड होल्शर, अक्सर अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुभाग में संचालन करने के लिए पॉलिमर इंजीनियरों की भर्ती करती है। 7 से 8 साल के कार्य अनुभव वाले लोग एलाइड सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स/बिजनेस डेवलपमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ आप 35,000/- से रु।50,000/- प्रति माह तक की सैलरी पा सकते हैं। अपोलो टायर्स लिमिटेड, सिएट लिमिटेड आदि जैसी टायर कंपनियों को भी पॉलिमर इंजीनियर्स की जरूरत है। पॉलीमर इंजीनियरिंग में स्नातकों के लिए क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर्स/ टेक्नोलॉजिस्ट, पॉलीमर स्पेशलिस्ट आदि सामान्य जॉब प्रोफाइल हैं।

प्रतिभावान विद्यार्थियों को तराशती योजना
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा

नेशनल टेलेंट सर्च यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एनसीईआरटी की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाना और उनकी प्रतिभा को बढ़ाना है। इसके तहत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन और विधि जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह योजना प्रतिभावान विद्यार्थियों को मासिक स्कॉलरशिप के रूप में आर्थिक मदद दे कर सहयोग देती है। इस योजना में बेसिक साइंस, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य के पाठ्यक्रमों के लिए पीएचडी स्तर तक सहायता प्रदान की जाती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन एवं विधि के लिए पीजी स्तर तक सहायता दी जाती है। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कक्षा 8 स्तर पर किया जाता है।

स्कॉलरशिप

परीक्षा आयोजन के आधार पर कक्षा 8 की परीक्षाओं के लिए बैठे छात्रों के प्रत्येक समूह के लिए 1000 स्कॉलरशिप दी जाती हैं। स्कॉलरशिप की राशि प्रत्येक माह 500 रुपए होती है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत और विकलांग छात्रों के लिए 3 प्रतिशत स्कॉलरशिप आरक्षित होती है। स्कॉलरशिप का भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता को न देकर संबद्ध संस्थान के प्रमुख के माध्यम से दिया जाता है।

चयन प्रक्रिया

प्रतिभाओं की पहचान दो स्तरीय लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती है। प्रथम स्तर का चयन अलग-अलग राज्य/यूनियन टेरेटरीज द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। प्रथम स्तर की परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही एनसीईआरटी द्वारा संचालित द्वितीय स्तर की परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र माने जाते हैं। राज्य और यूनियन टेरेटरीज राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना की प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा के साथ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना की भी परीक्षा आयोजित करते हैं।

पात्रता

मान्यताप्राप्त विद्यालयों के 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी उस राज्य/यूनियन टेरेटरी द्वारा संचालित प्रथम स्तर की परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं, जिस राज्य में विद्यालय स्थित है।

आवेदन प्रपत्र

आवेदन-प्रपत्र प्राप्त करने के लिये राज्य संपर्क अधिकारी से संपर्क करें। आवेदन-प्रपत्र एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन प्रपत्र विद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि तथा प्रपत्र कहां जमा कराया जायेगा, इस संबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के संपर्क अधिकारी से पता किया जा सकता है। विभिन्न राज्यों की आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां भिन्न हो सकती हैं।

शुल्क

एनसीईआरटी द्वारा द्वितीय स्तर की परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। राज्य और यूनियन टेरेटरी प्रथम परीक्षा के लिए अपेक्षित शुल्क के भुगतान के लिए अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इसलिये आवेदन प्रपत्र जमा करने से पहले कितनी और कैसे फीस दी जायेगी, इसका पता अपने राज्य संपर्क अधिकारी से लगा लेना चाहिए।

परीक्षा माध्यम

परीक्षा हिन्दी व अंग्रेजी के साथ असमी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में संचालित की जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र में जिस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, उस विकल्प का उल्लेख करें। इसके आधार पर ही अभ्यर्थी को उस भाषा में प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी।

परीक्षा-विधि

8वीं के लिए लिखित परीक्षा की विधि इस प्रकार है-प्रथम स्तर की राज्य/ यूनियन टेरेटरी स्तर पर संचालित परीक्षा में दो भाग होंगे (अ) मानसिक योग्यता परीक्षण (एमएटी) और (ब) शैक्षिक योग्यता परीक्षण (एसएटी)। इनमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषय शामिल होंगे। द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय स्तर पर संचालित परीक्षा में (अ) मानसिक योग्यता परीक्षण (एमएटी) और (ब) शैक्षिक योग्यता परीक्षण (एसएटी) शामिल होंगे। इनमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषय शामिल होंगे। (स) इंटरव्यू - इंटरव्यू के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर संचालित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा में प्रथम भाग एमएटी और द्वितीय भाग एसएटी शामिल होंगे। दोनों परीक्षाएं एक छोटे से अंतराल पर अलग-अलग ली जाएंगी। मानसिक योग्यता परीक्षा-एमएटी - चार विकल्पों सहित इसमें 90 मल्टीच्वॉइस प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। समय 90 मिनट होगा।

स्कॉलरशिप पाने की सामान्य शर्तें

स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो। वह अच्छा आचरण बनाए रखता हो (संस्थान प्रमुख द्वारा प्रमाणित) और अपना अध्ययन एक नियमित विद्यार्थी के रूप में कर रहा हो। बिना उचित अवकाश के अनुपस्थित न होता हो। पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करता हो। कोई रोजगार नहीं करता हो। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना पीएचडी कोर्स को छोड़ कर छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को कोई अन्य स्कॉलरशिप स्वीकार करने से वंचित नहीं करती, अलबत्ता किसी भी पाठ्यक्रम के लिए विदेश में अध्ययन के लिए कोई स्कॉलरशिप उपलब्ध नहीं होगी। यदि कोई प्राप्तकर्ता पंजीकरण/प्रवेश के एक माह के अंदर अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ता है तो उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी।

विजुअल मर्चेंडाइजिंग के क्षेत्र में हैं अपार संभावनाएं

विजुअल मर्चेंडाइजिंग शब्द भले ही कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन सेल्स और एडवरटाइजिंग के क्षेत्र से जुड़े लोग इससे भली-भांति वाकिफ हैं। विजुअल मर्चेंडाइजिंग वास्तव में एक आर्ट है, जिसमें एक व्यक्ति किसी प्रॉडक्ट या सर्विस को क्लाइंट्स के सामने कुछ इस तरह पेश करता है ताकि वह सेल्स को बढ़ावा दे सके। अब इस कॉन्सेप्ट को रिटेल सेक्टर में एक मार्केटिंग टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस क्षेत्र में वह सभी गतिविधियां शामिल हैं, जो रिटेल स्टोर्स में उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में मदद करती हैं। उदाहरण के तौर पर, प्रॉडक्ट के संभावित ग्राहकों के माइंड को समझना और उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में शिक्षित करना व प्रॉडक्ट को बेहद इफेक्ट व क्रिएटिव तरीके से पेश करना आदि। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस करियर के बारे में

क्या है विजुअल मर्चेंडाइजिंग

एजुकेशन एक्सपर्ट बताते हैं कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विजुअल मर्चेंडाइजर कहा जाता है। विजुअल मर्चेंडाइजर ऐसे पेशेवर हैं जो किसी भी ब्रांड, एक चेहरे को देने के लिए जिम्मेदार हैं। वे ऑनलाइन शॉपर्स और रिटेल स्टोर दोनों के लिए विंडो और स्टोर डिस्प्ले में अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन करते हैं। वे स्टोर थीम की योजना बनाते हैं, डिस्प्ले के लिए प्रॉपर की व्यवस्था करते हैं, डिस्प्ले फिक्स्चर और लाइटिंग की व्यवस्था करते हैं, ओपनिंग से पहले स्टोर सेट करते हैं, फ़्लोर प्लान के साथ काम करते हैं और डिस्प्ले को बनाने के लिए सेल्स फ़्लोर पर स्टोर कर्मियों को प्रशिक्षित करते हैं। एक विजुअल मर्चेंडाइजर का मुख्य उद्देश्य स्टोर की छवि के अनुरूप डिस्प्ले बनाना और अधिक ग्राहकों को स्टोर में लाना है।

शैक्षणिक योग्यता

आजकल ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग से संबंधित सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। इस कोर्स को करने के लिए छात्र का 12वीं पास होना आवश्यक है। हालांकि अधिकतर जगहों पर विजुअल मर्चेंडाइजिंग को फैशन डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स के तहत पढ़ाया जाता है।

कॅरियर एक्सपर्ट के अनुसार, विजुअल मर्चेंडाइजिंग के कोर्स में छात्रों को विजुअल मर्चेंडाइजिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है जैसे कि रिटेल स्टोर का लेआउट और डिजाइन, इंटीरियर डेकोरेशन, स्टोर के अंदर फर्नीचर और फिक्स्चर की स्थापना, स्टोर डिस्प्ले और उत्पादों की प्रस्तुति, विभिन्न संचार साधनों के उपयोग के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करना।

व्यक्तिगत गुण

इस क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों में डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी के गुण का होना बेहद आवश्यक है। एक विजुअल मर्चेंडाइजर में बेहतरीन आर्गेनाइजिंग स्किल्स होने के साथ-साथ प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व टाइम मैनेजमेंट आदि विशेषताएं भी होनी चाहिए। इसके अलावा उनमें संचार व इंटरपर्सनल स्किल्स, समस्या सुलझाने की क्षमता और कंप्यूटर का ज्ञान होना भी जरूरी है। कॅरियर एक्सपर्ट कहते हैं कि विजुअल मर्चेंडाइजर को उपभोक्ताओं के मनोविज्ञान को जानना आना चाहिए और उसे रूझानों का भी पूर्वानमान लगा लेना चाहिए।

संभावनाएं

शॉपिंग मॉल, फाइव स्टार होटल, बुटीक व रिटेल आउटलेट्स की संख्या बढ़ने के साथ ही विजुअल मर्चेंडाइजर्स की मांग में भी काफी इजाफा हुआ है। विजुअल मर्चेंडाइजर फैशन बुटीक, शॉपिंग मॉल, एम्पोरिया, डिजाइन कंपनी, आर्किटेक्चर फर्म, थीम पार्टी ऑर्गनाइजिंग कंपनी आदि में जॉब कर सकते हैं। वे प्रदर्शनियों, मेलों, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, अवार्ड सेरेमनी, मॉल, रिटेल में विंडो डिस्प्ले के लिए अनुबंध के आधार पर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में एक फ्रेशर भी दस से पंद्रह हजार आसानी से कमा सकता है। वहीं कुछ समय के अनुभव के बाद आप किसी बड़े ब्रांड के रिटेल आउटलिट में काम कर सकते हैं और एक आकर्षक पैकेज पा सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बैंगलोर
- द सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई
- स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज, कोच्चि
- बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा

डिजिटल क्रांति के दौर में बढ़ते साइबर अपराध, बड़ी चुनौती

ललित गर्ग

डिजिटल व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है। जब कोई नागरिक मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन करता है, यूपीआई से भुगतान करता है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश करता है, तब वह केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल तंत्र की विश्वसनीयता पर भरोसा करता है। यदि यही भरोसा लगातार साइबर ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग, नितांत व्यक्तिगत सूचनाओं के सार्वजनिक होने के भय, निवेश घोटालों और पहचान की चोरी जैसी घटनाओं से टूटने लगे, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर पड़ जाएगी।

डिजिटल क्रांति ने भारत को अभूतपूर्व गति, सुविधा और पारदर्शिता प्रदान की है। आज मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने सामान्य नागरिक के जीवन को सरल और सक्रिय बनाया है। भारत विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से उभर रहा है और 'डिजिटल इंडिया' तथा 'विकसित भारत-2047' का सपना इसी तकनीकी परिवर्तन पर आधारित है। किंतु इस उजले परिदृश्य के समानांतर एक भयावह अंधेरा भी तेजी से फैल रहा है-साइबर अपराधों का बढ़ता साम्राज्य। डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन वित्तीय ठगी, फिशिंग, पहचान की चोरी, निवेश घोटाले, व्यक्तिगत गोपनीयता पर सेंध, सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध, बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग आज केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक नैतिकता के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। विडंबना यह है कि जिस तकनीक का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सुरक्षित, सुविधाजनक और ज्ञानसमृद्ध बनाना था, वही तकनीक अपराधियों के लिए सबसे प्रभावी हथियार बनती जा रही है। इंटरनेट की असीम संभावनाओं का लाभ जितनी तेजी से समाज ने उठाया है, उतनी ही तेजी से अपराधियों ने भी उसे अपने हित में ढाल लिया है। परिणामस्वरूप डिजिटल दुनिया में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है।

डिजिटल व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है। जब कोई नागरिक मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन करता है, यूपीआई से भुगतान करता है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश करता है, तब वह केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल तंत्र की विश्वसनीयता पर भरोसा करता है। यदि यही भरोसा लगातार साइबर ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग, नितांत व्यक्तिगत सूचनाओं के सार्वजनिक होने के भय, निवेश घोटालों और पहचान की चोरी जैसी घटनाओं से टूटने लगे, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर पड़ जाएगी। जिस प्रकार नकली मुद्रा का प्रसार पूरी आर्थिक व्यवस्था को संकट में डाल देता है, उसी प्रकार डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ना कैशलेस अर्थव्यवस्था की अवधारणा को कमजोर कर सकता है। परंपरागत अपराधों और साइबर अपराधों में मूलभूत अंतर है। पहले अपराध किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित रहते थे, अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती थी। आज साइबर अपराधी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। उसके लिए

जोखिम न्यूनतम और लाभ अधिकतम है। यही असंतुलन साइबर अपराध को अत्यंत खतरनाक बनाता है। अपराध का यह नया स्वरूप सीमाओं, भाषाओं और कानूनों की पारंपरिक सीमाओं को भी चुनौती दे रहा है।

चिंता केवल आर्थिक अपराधों तक सीमित नहीं है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया मंचों पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रचार-प्रसार के आरोपों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यदि लोकप्रिय डिजिटल मंचों पर पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन प्रसारित हो सकते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक विफलता भी है। प्रश्न यह भी है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां केवल स्वयं को तकनीकी मंच कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती हैं? जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिद्म यह तय करते हैं कि कौन-सा विज्ञापन किस व्यक्ति तक पहुंचेगा, तब उन मंचों की जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। आज अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक सामग्री हटाने का दावा करते हैं, किंतु व्यवहार में उनकी प्राथमिकता कई बार राजस्व और व्यावसायिक हित प्रतीत होती है। यदि बाल यौन शोषण, अश्लीलता, साइबर ठगी या संगठित अपराध से जुड़े विज्ञापन और सामग्री लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं, तो यह केवल अपराधियों की सफलता नहीं, बल्कि डिजिटल मंचों की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए बिना डिजिटल समाज स्वस्थ नहीं रह सकता।

साइबर अपराध का सबसे दुखद पक्ष पीड़ित की मानसिक पीड़ा है। जीवनभर की बचत कुछ मिनटों में गायब हो जाती है। इसके बाद पुलिस, बैंक और साइबर हेल्पलाइन के चक्कर लगते हैं, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अधिकांश मामलों में धन वापस नहीं मिल पाता। इससे नागरिक के भीतर व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। यदि अपराधी को दंड न मिले और पीड़ित को राहत न मिले, तो कानून का भय भी समाप्त होने लगता है। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन, साइबर क्राइम समन्वय केंद्र तथा डिजिटल सुरक्षा संबंधी अनेक पहलें शुरू की गई हैं। न्यायपालिका ने भी ऑनलाइन धोखाधड़ी को आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर गंभीर चिंता व्यक्त की है। फिर भी नीति और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच बड़ी दूरी दिखाई देती है। शिकायत दर्ज होने के बाद शुरूआती कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इसी अवधि में बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएं और धन के प्रवाह को रोक दिया जाए तो बड़ी राशि बचाई जा सकती है। लेकिन अक्सर कार्रवाई में देरी अपराधियों के पक्ष में चली जाती है।

डिजिटल सुरक्षा अब केवल पुलिस का विषय नहीं रही। यह आर्थिक नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा बहुआयामी प्रश्न बन चुकी है। विकसित देशों ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के समान महत्व दिया है। विशेष एजेंसियां, अत्याधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित विशेषज्ञ, रियल टाइम डेटा साझा करने की व्यवस्था और कठोर दंडात्मक कानून वहां की व्यवस्था का हिस्सा हैं। भारत को भी इसी दिशा में और अधिक सुदृढ़ कदम उठाने होंगे। स्थानीय पुलिस को डिजिटल फॉरेंसिक, ब्लॉकचेन विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जांच और अंतरराष्ट्रीय साइबर कानूनों का प्रशिक्षण देना समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही नागरिक जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। तकनीक जितनी उन्नत होगी, अपराधी भी उतने ही नए तरीके खोजेंगे। इसलिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को जनआंदोलन बनाया जाना चाहिए। लोगों को संदिग्ध लिंक, फर्जी कॉल, निवेश योजनाओं और सोशल मीडिया के छल-प्रपंचों से बचने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि सुरक्षा का पूरा दायित्व नागरिक पर डालकर सरकार, बैंक और डिजिटल कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकतीं। सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराना संस्थागत दायित्व है।

भ्रष्टाचार, लापरवाही और कमजोर केवाईसी व्यवस्था भी साइबर अपराध को बढ़ावा देती है। यदि फर्जी पहचान के आधार पर बैंक खाते खुलते हैं, यदि भुगतान प्लेटफॉर्म समय पर संदिग्ध लेन-देन नहीं रोकते, यदि आंतरिक मिलीभगत से अपराधियों को सुविधा मिलती है, तो यह केवल तकनीकी दोष नहीं बल्कि संस्थागत अपराध है। इसलिए पारदर्शी ऑडिट, कठोर उत्तरदायित्व और सख्त दंड व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। साइबर अपराध अब किसी एक देश की समस्या नहीं रहा। इंटरनेट की दुनिया में अपराधी सीमाओं से मुक्त हैं, इसलिए समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व की प्रमुख शक्तियों को साइबर अपराध के विरुद्ध साझा कानूनी ढांचा, त्वरित सूचना आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग विकसित करना होगा। जिस प्रकार आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग आवश्यक माना गया, उसी प्रकार साइबर अपराध के विरुद्ध भी विश्वव्यापी समन्वय समय की मांग है।

अंततः डिजिटल क्रांति का वास्तविक उद्देश्य केवल तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि मानव जीवन को अधिक सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक बनाना है। यदि यही क्रांति भय, असुरक्षा और अविश्वास का कारण बनने लगे, तो उसकी सफलता अधूरी रह जाएगी। डिजिटल भारत की वास्तविक शक्ति उसके ऐप्स, सर्वरों और आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में निहित है, जिसके साथ करोड़ों नागरिक प्रतिदिन अपने मोबाइल पर एक-एक लेन-देन करते हैं। आज आवश्यकता केवल तकनीकी समाधान की नहीं, बल्कि तकनीक, नैतिकता, कानून और उत्तरदायित्व के समन्वित मॉडल की है। सरकार को कठोर कानून, त्वरित न्याय और सक्षम जांच तंत्र विकसित करना होगा, डिजिटल कंपनियों को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना होगा, वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ानी होगी और नागरिकों को डिजिटल अनुशासन अपनाना होगा। साइबर अपराध और भारतीय डिजिटल जीवनशैली के बीच संतुलन ही विकसित भारत की सबसे बड़ी कसौटी है। यदि यह संतुलन स्थापित हो गया, तो डिजिटल भारत विश्व का सबसे विश्वसनीय डिजिटल लोकतंत्र बन सकता है, अन्यथा तकनीकी उपलब्धियां भी अविश्वास के बोझ तले दम तोड़ देंगी।

संपादकीय

विश्वास बहाली जरूरी

देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था-विश्वास को आहत करने वाला चंदा-चोरी प्रकरण सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में आखिरकार महामंत्री चंपत राय व सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। अब ट्रस्ट के अन्य सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री बनाया गया है। राममंदिर के चंदे में हेरफेर से उठे देशव्यापी विवाद के बाद प्राथमिकी दर्ज होने, एसआईटी के गठन और कुछ गिरफ्तारियों के बाद ये इस्तीफे अपरिहार्य थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ दो इस्तीफों से श्रद्धालुओं के भरोसे की बहाली हो पाएगी? जैसा कि नवनियुक्त अंतरिम महामंत्री कृष्ण मोहन ने कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि चंदा चोरी के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा,उसे कड़ी सजा मिले। उन्होंने स्वीकारा कि ट्रस्ट प्रबंधन और संचालन में कहीं न कहीं खामियां रही हैं। उन्हें दूर करने का प्रयास होगा। साथ ही माना कि जो तथ्य सामने आए हैं उससे न्यास की छवि धूमिल हुई है। एक अविश्वास का भाव उत्पन्न हुआ। ट्रस्ट की प्रतिष्ठा को फिर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा में शामिल होने से पहले कुछ सालों तक परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु वैज्ञानिक भी रहे हैं। वे दलित समुदाय से आते हैं। वे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने सोमवार को अयोध्या में उन बहुमूल्य वस्तुओं को मीडिया के सामने प्रदर्शित किया, जिनके गायब होने को लेकर अटकलें लगायी जा रही थीं। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के संचालन के लिये विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक बाईस जुलाई को होगी। जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिये जाने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि तब तक चंदा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आस्था व विश्वास से खिलवाड़ के कृत्य की जांच के लिये क्या एसआईटी की जांच पर्याप्त है? क्या चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे मात्र से उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदार व्यवहार पर कार्रवाई पूरी मान ली जाए? क्या इतनी कार्रवाई मात्र से सारे प्रकरण से संदेह के बादल छंट जाएंगे और लोगों का खंडित भरोसा फिर से कायम हो जाएगा? अब तो संघ प्रमुख ने भी स्वीकारा है कि इस घटनाक्रम से व्यापक हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।

चिंतन-मनन

तुम्हारी सम्पदा है निष्ठा

यदि तुम सोचने हो कि ईश्वर में तुम्हारी निष्ठा ईश्वर का कुछ हित कर रही है, तो यह भूल है। ईश्वर या गुरु में तुम्हारी निष्ठा ईश्वर या गुरु का कुछ नहीं करती। निष्ठा तुम्हारी सम्पदा है। निष्ठा तुम्हें बल देती है। तुममें स्थिरता, केंद्रीयता, प्रशांति और प्रेम लाती है। निष्ठा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। यदि तुममें निष्ठा का अभाव है, तुम्हें निष्ठा के लिए प्रार्थना करनी होगी। परन्तु प्रार्थना के लिए निष्ठा की आवश्यकता है यह विरोधाभासी है। लोग संसार में निष्ठा रखते हैं परन्तु समस्त संसार सिर्फ साबुन का बुलबुला है। लोगों की स्वयं में निष्ठा है परन्तु वे नहीं जानते कि वे स्वयं कौन हैं! लोग सोचते है कि ईश्वर में उनकी निष्ठा है परन्तु वे सचमुच नहीं जानते कि ईश्वर कौन है। निष्ठा तीन प्रकार की होती है- पहली है स्वयं में निष्ठा- स्वयं में निष्ठा के बिना तुम सोचते हो, मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं, मैं कभी इस जिंदगी से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। दूसरी है संसार में निष्ठा- संसार में तुम्हें निष्ठा रखनी ही होगी वरना तुम एक इन्च भी नही बढ़ सकते। यदि तुम सब पर शक करोगे, तब तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तीसरे ईश्वर में निष्ठा रखो, तभी तुम विकसित होगे। ये सभी निष्ठाएं आपस में जुड़ी हैं।प्रत्येक को मजबूत होने के लिए तुममें तीनों ही होनी चाहिए। यदि तुम एक पर भी शक करोगे, तुम सब पर शक करना आरम्भ कर दोगे। ईश्वर, संसार और स्वयं के प्रति निष्ठा का अभाव भय लाता है। निष्ठा तुम्हें पूर्ण बनाती है-सम्पूर्ण संसार के प्रति निष्ठा होते हुए भी ईश्वर में निष्ठा न होने से पूर्ण शान्ति नहीं मिलती। यदि तुममें निष्ठा और प्रेम है तो स्वतः ही तुममें शांति और स्वतत्रता होगी।अत्यधिक अशान्त व्यक्तियों को समस्याओं से निकलने के लिए ईश्वर में निष्ठा रखनी चाहिए। निष्ठा और विश्वास में फर्क है। निष्ठा आरम्भ है, विश्वास परिणाम है। स्वयं के प्रति निष्ठा स्वतंत्रता लाती है। संसार में निष्ठा तुम्हें मन की शांति देती ह। ईश्वर में निष्ठा तुममें प्रेम जागृत करती है।

धर्म का धन : श्रद्धा की अमानत, स्वार्थ का साधन नहीं

श्रमण डॉ पुष्पेन्द्र

समाज की सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है, तो वह उसकी आस्था है। धन, सत्ता, ज्ञान और संसाधन समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु जिस समाज की आस्था जीवित रहती है, वह समाज हर संकट से उबरने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि मंदिर, स्थानक, तीर्थ, उपाश्रय और धर्मस्थल केवल ईंट-पत्थरों से निर्मित भवन नहीं होते, बल्कि वे करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, तप, त्याग और विश्वास के जीवंत केंद्र होते हैं।

एक श्रद्धालु जब धर्मस्थल में प्रवेश करता है, तो वह केवल पूजा करने नहीं आता; वह अपने मन की व्यथा, आशा, कृतज्ञता और विश्वास भी वहीं अर्पित करता है। उसकी दक्षिणा केवल मुद्रा नहीं होती, बल्कि उसकी मेहनत की कमाई, उसके परिवार का विश्वास और धर्म के प्रति उसका समर्पण होता है। इसलिए धर्मस्थलों में आने वाला प्रत्येक अंश समाज की अमानत है।

दुर्भाग्य तब उत्पन्न होता है, जब धर्म के नाम पर प्राप्त धन या संसाधनों का उपयोग धर्म के उद्देश्य से हटकर व्यक्तिगत लाभ, वैभव, प्रतिष्ठा या स्वार्थ के लिए होने लगे। यह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं होती, बल्कि समाज की आस्था पर कुठाराघात होता है। जिस धन में हजारों श्रद्धालुओं की भावनाएँ जुड़ी हों, उसका दुरुपयोग केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि आत्मा और अंतरात्मा का भी विषय है।

इतिहास साक्षी है कि धर्म का धन कभी किसी को स्थायी सुख नहीं दे पाया। जो संपत्ति छल, विश्वासघात या धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अर्जित होती है, वह बाहर से भले वैभव का प्रदर्शन करे, पर भीतर शांति नहीं दे सकती। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि अनुचित साधनों से प्राप्त धन अंततः विनाश का कारण बनता है। धर्म के धन के संदर्भ में यह बात और भी अधिक सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें केवल धन नहीं, असंख्य लोगों की श्रद्धा समाहित होती है। जैन दर्शन के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने मानवता को संयम, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का अमूल्य संदेश दिया। इनमें अपरिग्रह का सिद्धांत विशेष रूप से आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। अपरिग्रह का अर्थ केवल अधिक वस्तुएँ न रखना नहीं है; इसका वास्तविक अर्थ है—लोभ, स्वार्थ, संग्रह की मानसिकता और अधिकार के दुरुपयोग से स्वयं को मुक्त करना।

यदि धर्म से जुड़े व्यक्ति ही अपरिग्रह को भूल जाएँ और धर्म को संग्रह, प्रभाव या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का साधन बना लें, तो भगवान महावीर के संदेश का सार ही समाप्त हो जाता है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को बड़ा बनाना नहीं, बल्कि उसके अहंकार को छोटा करना है। धर्म हमें अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व सिखाता है; संग्रह नहीं, समर्पण सिखाता है; स्वार्थ नहीं, सेवा का मार्ग दिखाता है। धर्मस्थलों का निर्माण समाज के सहयोग से होता है। एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी-सी बचत से दान देता है, कोई किसान अपनी उपज का अंश अर्पित करता है, कोई व्यापारी अपनी आय का हिस्सा धर्मकार्य में लगाता है। सभी की भावना एक ही होती है—धर्म जीवित रहे, संस्कृति सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियाँ भी इन मूल्यों से जुड़ी रहें। ऐसे में यदि उस विश्वास को ठेस पहुँचती है, तो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज आहत होता है।

आज आवश्यकता आरोप लगाने या विवाद बढ़ाने की नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि की है। धर्मस्थलों का संचालन पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी और उत्तरदायित्व के साथ होना चाहिए। आय-व्यय का स्पष्ट लेखा-जोखा, समाज के प्रति जवाबदेही और धर्म के उद्देश्य के अनुरूप संसाधनों का उपयोग—ये केवल प्रशासनिक व्यवस्थाएँ नहीं, बल्कि धार्मिक मर्यादाएँ हैं। समाज को भी यह समझना होगा कि धर्म की रक्षा केवल दान देने से नहीं होती, बल्कि धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने से होती है। जहाँ पारदर्शिता है, वहाँ विश्वास बढ़ता है; जहाँ विश्वास बढ़ता है, वहीं धर्म फलता-फूलता है। यदि कहीं त्रुटि दिखाई दे, तो उसका समाधान भी धर्मसम्मत, संयमित और संवादपूर्ण तरीके से होना चाहिए। कटुता, आरोप और वैमनस्य किसी भी धार्मिक वातावरण को शुद्ध नहीं बना सकते।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्ति से बड़ा धर्म है, पद से बड़ी मयार्दा है और संस्था से बड़ी आस्था है। व्यक्ति बदल सकते हैं, व्यवस्थाएँ बदल सकती हैं, परंतु धर्म और उसकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहनी चाहिए। यदि धर्म की पवित्रता सुरक्षित रहेगी, तो समाज का विश्वास भी अडिग रहेगा।

भगवान महावीर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव संग्रह में नहीं, त्याग में है; अधिकार में नहीं, उत्तरदायित्व में है; और बाहरी संपत्ति में नहीं, अंतःकरण की निर्मलता में है। यही संदेश आज प्रत्येक धार्मिक संस्था, प्रत्येक पदाधिकारी और प्रत्येक श्रद्धालु के लिए समान रूप से प्रासंगिक है।

आइए, संकल्प लें कि धर्म को कभी स्वार्थ का साधन नहीं बनने देंगे। मंदिर, स्थानक और तीर्थ केवल भवन नहीं, हमारी आत्मा के प्रतीक हैं। उनकी पवित्रता, पारदर्शिता और मयार्दा की रक्षा करना हम सभी का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है। जब धर्म शुद्ध रहेगा, तभी समाज सुदृढ़ रहेगा; और जब आस्था सुरक्षित रहेगी, तभी संस्कृति अमर रहेगी।

पंजाब ने बड़ी कीमत देकर शांति पाई, सतलुज के जरिये पुराने जख्मों को कुरेदना गलत है

नीरज कुमार दुबे

पंजाब के अशांत दौर, राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की बहस के बीच एक बार फिर विवादों के केंद्र में आई फिल्म सतलुज ने देशभर में तीखी बहस छेड़ दी है। अभिनेता दिलजीत दोसांझ अभिनीत यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। लेकिन यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि पंजाब के उस संवेदनशील और खून से सने दौर की कहानी को दोबारा सामने लाने की कोशिश है, जब आतंकवाद, अलगाववाद और सीमापार से प्रायोजित हिंसा ने पूरे राज्य को भय और अस्थिरता में धकेल दिया था। ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इस फिल्म को भारत में ओटीटी मंच से हटाने का फैसला न केवल उचित दिखाई देता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी जिम्मेदार लोकतंत्र का कर्तव्य होता है।

हम आपको बता दें कि यह फिल्म पहले घल्लूघारा नाम से शुरू हुई थी। बाद में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की आपत्तियों के बाद इसका नाम पंजाब-95 रखा गया और अंततः इसे सतलुज नाम से प्रदर्शित किया गया। फिल्म की विषयवस्तु पंजाब पुलिस के आतंकवाद विरोधी अभियान और उस दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि जसवंत सिंह खालड़ा ने 1984 से लेकर 1994 के बीच हजारों अज्ञात शवों के कथित अंतिम संस्कार के मामलों की जांच की थी। बाद में उनका खुद का अपहरण हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। अदालत ने इस मामले में कुछ पुलिसकर्मियों को दोषी भी ठहराया था।

देखा जाये तो इन तथ्यों से किसी को इंकार नहीं हो सकता कि पंजाब ने उस दौर में अत्यंत पीड़ा झेली। हजारों निर्दोष लोग मारे गए, परिवार उजड़ गए और भय का वातावरण पूरे राज्य पर छाया रहा। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके दर्द के प्रति संवेदना व्यक्त करना हर संवेदनशील समाज का दायित्व है। लेकिन इसके साथ यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उस समय पंजाब किस परिस्थिति से गुजर रहा था, इसे भी ईमानदारी से समझा जाए। सीमापार से आतंकवाद को खुला समर्थन मिल रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां पंजाब को अस्थिर करने के लिए सक्रिय थीं। अलगाववादी संगठन खुलेआम हथियारबंद हिंसा चला रहे थे। पुलिसकर्मियों, पत्रकारों, नेताओं और आम नागरिकों की हत्याएं रोजमर्रा की खबर बन चुकी थीं।

ऐसे भयावह दौर में पंजाब पुलिस ने जिस कठोर अभियान को चलाया, उसी के कारण राज्य धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट सका। उस समय के पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल को लेकर आज अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर पंजाब पुलिस और सुरक्षा बल कठोर कार्रवाई नहीं करते, तो शायद पंजाब आज भी आतंकवाद की आग में झुलस रहा होता। जिन्होंने उस दौर को अपनी आंखों से देखा है, वह जानते हैं कि हालात कितने गंभीर थे। केपीएस गिल और उनकी टीम ने आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसी ने पंजाब को अलगाववाद और बंदूक की राजनीति से बाहर निकालने में निर्णायक भूमिका निभाई। आज कुछ राजनीतिक दल और कथित बुद्धिजीवी पुलिसिया कार्रवाई को केवल एकतरफा तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि उस समय पंजाब में किस दल की सरकार थी। उस समय राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सत्ता किसके हाथ में थी और निर्णय कहां से लिए जाते थे, यह इतिहास का हिस्सा है। साथ ही जो लोग आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हैं, उन्हें अपने अतीत में भी झांकना चाहिए। खासतौर पर कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि आपातकाल के दौरान देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों कुचल दी गई थी? अखबारों पर सेंसरशिप क्यों लगाई गई थी? विपक्षी नेताओं को जेलों में क्यों डाला गया था? यदि आज कोई सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कोई कदम उठाती है, तो उसे तानाशाही कहना इतिहास के साथ अन्याय होगा। इसी के साथ पंजाब में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी की भूमिका पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। जिस तरह उसके कुछ नेता सतलुज फिल्म के पक्ष में खुलकर बयान दे रहे हैं, उससे यह आशंका भी पैदा होती है कि कहीं यह प्रयास राज्य सरकार की कथित नाकामियों से जनता का ध्यान हटाने की रणनीति तो नहीं है। कहीं आम आदमी पार्टी यह तो नहीं चाहती कि विधानसभा चुनावों में उसके कामकाज की बजाय इतिहास की घटनाएं ही मुद्दा बन जायें? सभी को यह समझना होगा कि इतिहास से सीख लेना आवश्यक है, लेकिन इतिहास को वर्तमान पर इस तरह हावी कर देना कि भविष्य ही प्रभावित होने लगे, किसी भी राज्य और समाज के लिए उचित नहीं माना जा सकता। पंजाब को आज विकास, रोजगार, नशे के खिलाफ कड़े कदम और कानून व्यवस्था सुधारने जैसे वास्तविक मुद्दों पर आगे बढ़ने की जरूरत है, न कि पुराने घावों को बार बार कुरेदकर राजनीतिक लाभ लेने की। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पंजाब कोई सामान्य राज्य नहीं, बल्कि देश का सीमावर्ती और अत्यंत संवेदनशील प्रदेश है। यहां के सामाजिक और धार्मिक तानेबाने को बिगाड़ने की कोशिशें पहले भी होती रही हैं और आज भी दुश्मन ताकतें मौके की तलाश में रहती हैं। ऐसे में पुराने घावों को इस प्रकार कुरेदना, जिससे समाज में नई वैमनस्यता पैदा हो, बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि किसी भी संवेदनशील विषय को बिना व्यापक सामाजिक परिणामों पर विचार किए प्रस्तुत कर दिया जाए।

फिल्म के प्रदर्शन को लेकर जिस प्रकार विवाद बढ़ा, उसने यह भी दिखाया कि ओटीटी मंचों के लिए स्पष्ट और कठोर नियमों की आवश्यकता है। फिल्म को केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड ने अनेक कट लगाने के सुझाव दिए थे। पहले 21 कट और बाद में 120 से अधिक संशोधनों की बात सामने आई। इसके बावजूद फिल्म निमार्ताओं ने नया नाम देकर इसे ओटीटी मंच पर जारी कर दिया। ऐसे में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना स्वाभाविक था। यदि किसी सामग्री से सामाजिक तनाव या अलगाववादी भावनाओं को हवा मिलने की आशंका हो, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह समय रहते कदम उठाए।

दिलचस्प बात यह भी रही कि अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने स्वयं पहले ही आशंका जता दी थी कि फिल्म को भारत में हटाया जा सकता है। बाद में उन्होंने लोगों से इसे डाउनलोड कर दूसरों को दिखाने की अपील भी की। यह रवैया कई सवाल खड़े करता है। जब मामला इतना संवेदनशील हो, तब जिम्मेदार कलाकारों को समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने का संदेश देना चाहिए, न कि विवाद को और भड़काने वाला व्यवहार करना चाहिए। यह सही है कि इतिहास के कठिन अध्यायों पर चर्चा होनी चाहिए। पीड़ितों को न्याय और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन किसी भी चर्चा का उद्देश्य समाज को बांटना नहीं, बल्कि सीख देना होना चाहिए। पंजाब ने बहुत खून बहते देखा है। वहां की नई पीढ़ी शांति, विकास और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार की ऐसी प्रस्तुति, जिससे अलगाववादी मानसिकता को बल मिले या सुरक्षा बलों के मनोबल पर आघात पहुंचे, उसे गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। बहरहाल, सरकार का निर्णय इसी व्यापक राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ऊपर राष्ट्र की एकता, सामाजिक सद्भाव और सीमावर्ती राज्यों की स्थिरता है। पंजाब ने कठिन संघर्ष के बाद शांति हासिल की है।

किसी दूसरे एक्टर से कभी नहीं हुआ इनसिक्योर

अभिषेक बच्चन ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में 26 साल पूरे किए हैं। उनकी पहली फिल्म 'रिफ्यूजी' 2000 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से करीना कपूर ने भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। हाल ही में एक बातचीत में अभिषेक ने अपने सफर को याद किया और बताया कि कैसे इतने साल में एक एक्टर के तौर पर उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।

अब कैमरे के सामने मैं कम्फर्टेबल हूं

अभिषेक ने एक एक्टर के तौर पर खुद में आए सबसे बड़े बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बस एक ही बदलाव आया है कि अब मैं ज्यादा कम्फर्टेबल महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि जब मैंने शुरुआत की थी, तो थोड़ी असहजता थी। लेकिन अब कैमरे के सामने मैं ज्यादा कम्फर्टेबल रहता हूं। जब आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और खुद में सहज महसूस करते हैं, तो आपको उन फैसलों के बारे में स्पष्टता मिलती है जो आपको लेने होते हैं। आज मैं बहुत स्पष्ट हूं या यूं कहूं कि पिछले पांच से सात साल से कि किसी खास समय पर मुझे क्या नहीं करना है। करियर की शुरुआत में बहुत उत्साह होता है और काम मिलेगा या नहीं, इसे लेकर असुरक्षा भी होती है। इसलिए जो भी काम मिलता है, आप उसे कर लेते हैं।

अभिषेक ने उन इनसिक्योरिटीज के बारे में भी बात की जिनका सामना अक्सर एक्टर्स को करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने साथियों की सफलता को लेकर कभी असुरक्षा महसूस क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं क्लियर होता हूं कि मुझे यह नहीं करना है। इसका मतलब है कि मैं निश्चित रूप से यह करना चाहता हूं। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा पक्का इरादा होता है और यह एक तरह की परिपक्वता और शांति से आता है। मुझे लगता है कि इससे आपके काम में भी मदद मिलती है। अब हम हर जगह नहीं भटकते। मैं कभी भी इस बात को लेकर इनसिक्योर एक्टर नहीं रहा कि 'वह क्या कर रहा है'। अपनी क्षमताओं को लेकर इनसिक्योर, हां। मुझे लगता है कि सभी एक्टर इस बात को लेकर इनसिक्योर होते हैं कि 'क्या मैं यह कर पाऊंगा?'

इन दिनों अभिषेक शाहरुख खान की आगामी फिल्म 'किंग' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस मच अवेटेड फिल्म में अभिषेक विलेन के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में एक बड़ी स्टारकास्ट नजर आएगी, जिसमें शाहरुख और अभिषेक के अलावा सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, राघव जुयाल, जयदीप अहलावत, अक्षय ओबेरॉय और रानी मुखर्जी सरीखे कई नाम शामिल हैं।

आकांक्षा रंजन का अनप्रिडिक्टेबल खेल जारी 'इक्का' में करेंगी सरप्राइज

आकांक्षा रंजन अब साफ़ तौर पर ये साबित कर रही हैं कि उन्हें अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से ज़रा भी डर नहीं लगता। हर नए प्रोजेक्ट के साथ वो कुछ ऐसा लेकर आती हैं जो उनके पिछले किरदार से बिल्कुल अलग होता है। इसी के चलते उनकी फिल्मोग्राफी अब एकदम रंग-बिरंगी और वर्सेटाइल बनती जा रही है। हाल ही में 'ग्राम चिकित्सालय सीज़न 2' में उन्होंने एक दिल छू लेने वाली, दयालु गांव की डॉक्टर — डॉ. गर्गी — का किरदार निभाकर खूब तारीफें बटोरी हैं। और अब आकांक्षा तैयार हैं दर्शकों को एकदम नया झटका देने के लिए, अपने आने वाले लीगल थ्रिलर 'इक्का' में। गांव की सादगी छोड़कर इस बार वो कोर्टरूम की तेज़-तर्रार दुनिया में एंट्री ले रही हैं, जहां वो एक मॉडर्न यंग वुमन के किरदार में नजर आएंगी — जो उनके काम में एक और नया तड़का जोड़ता है।

'इक्का' का ट्रेलर इस इंटेंस कहानी की एक झलक देता है। एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा के बैकड्रॉप पर बनी ये कहानी एक मशहूर वकील के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक मर्डर के आरोपी का केस लड़ना पड़ता है। हालांकि आकांक्षा के किरदार को लेकर मेकर्स ने अभी ज़्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन ट्रेलर ये इशारा ज़रूर करता है कि उनकी भूमिका कहानी में खास अहमियत रखती है। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने को लेकर आकांक्षा कहती हैं, 'मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि मैं अपने किरदार के ज़रिए क्या इम्पैक्ट ला सकती हूं। मैं काफी एक्साइटेड हूं कि अब दर्शक 'इक्का' की दुनिया की पहली झलक ट्रेलर के ज़रिए देख पाएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि थ्रिलर मेरा पसंदीदा जॉनर है, तो ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना मेरे लिए और भी रोमांचक था। मेकर्स की सोच और जिस तरह से स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई, उसने मुझे और भी खींच लिया। उनके विज़न में एकदम क्लैरिटी थी, और वही चीज़ मेरे साथ रह गई।' पिछले कुछ सालों में आकांक्षा ने जानबूझकर अलग-अलग जॉनर के प्रोजेक्ट्स चुने हैं। 'गिल्टी' और 'मोनिका, ओ माय डार्लिंग' में अपने दमदार परफॉर्मेंस से उन्होंने गहरी छाप छोड़ी, और फिर 'ग्राम चिकित्सालय' में डॉ. गर्गी बनकर अपना एक अलग ही सॉफ्ट और इमोशनल साइड दिखाया। अब 'इक्का' के साथ वो फिर एक नए स्पेस में कदम रख रही हैं — इस बार कहानी ज़्यादा डार्क और लेयर्ड है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो, इस समय 'ग्राम चिकित्सालय सीज़न 2' में अपने परफॉर्मेंस के लिए सराहना बटोर रहीं आकांक्षा जल्द ही 'इक्का' में नज़र आएंगी, जिसके बाद उनके पास कई और दिलचस्प प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं — जिनका खुलासा अभी बाकी है।

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को रिलीज होगी

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की आगामी फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। केवीएन प्रोडक्शंस ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया। प्रोडक्शन हाउस द्वारा शेयर किए गए पोस्टर पर लिखा था, '11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में। 60 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन लेकर आ रहे हैं 'हैवान'।' 'हैवान' एक दमदार थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आएगी। फिल्म में श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी।

केवीएन प्रोडक्शन और थेस्पियन फिल्म्स प्रोडक्शन की फिल्म 'हैवान' को वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने प्रोड्यूस किया है। इस बीच, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने हाल ही में फिल्म 'भूत बंगला' के लिए फिर से साथ काम किया है। इस फिल्म में परेश रावल, जिशु सेनगुप्ता, राजपाल यादव, तब्बू, वामिका गब्बी और असरानी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। 'भूत बंगला' 2007 में रिलीज हुई 'भूल भुलैया' के बाद प्रियदर्शन की दूसरी हिंदी हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी और मनोज जोशी ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। यह फिल्म 2026 की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन चुकी है।

अक्षय कुमार की हालिया फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' है। यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन अहमद खान ने किया है। फिल्म में एक बड़ी स्टार कास्ट है, जिसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, तुषार कपूर और सयाजी शिंदे जैसे नाम शामिल हैं।

अगली फिल्म के लिए कई लुक अपनाएंगे सलमान

सलमान खान अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग में काफी व्यस्त हैं। फिल्म में सलमान खान एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म का फैंस को काफी इंतजार है। एक पॉडकास्ट के दौरान फिल्म के निर्माता दिल राजू ने फिल्म को लेकर काफी कुछ बताया। हाल ही में दिल राजू एक पॉडकास्ट पर पहुंचे थे। जहां उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'मुझे वामसी पेडिपल्ली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म पर बहुत भरोसा है। यह अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा।' इसके अलावा दिल राजू ने बताय कि यह सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म होगी। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और काफी कुछ होगा। पॉडकास्ट के दौरान दिल राजू ने यह भी बताया कि इस फिल्म में सलमान कई अलग-अलग लुक में नजर आएंगे। वहीं फिल्म के शूटिंग शेड्यूल की जानकारी देते हुए निर्माता दिल राजू ने कहा, 'यह फिल्म अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। हमें इसके ब्लॉकबस्टर होने की पूरी उम्मीद है। सलमान भी इसकी शूटिंग के मजे ले रहे हैं। फिल्म में भरपूर हीरोइज्म और 'वाउ फैक्टर' होगा।

ईद पर रिलीज हो सकती है फिल्म

फिल्म श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स बैनर तले बन रही है। वहीं फिल्म का निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है। कुछ दिनों पहले ही सलमान और नयनतारा को मेकर्स के साथ मुहूर्त सेरेमनी में देखा गया था। इन दिनों वो इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म की बाकी कास्ट की जानकारी मेकर्स ने नहीं दी। अब दिल राजू की मानें तो इसकी शूटिंग अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। अब मेकर्स इस फिल्म को ईद 2027 तक रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं।

मैं ट्रेंड्स को फॉलो वालों में से नहीं हूं

सेलिब्रिटी पर हमेशा ट्रेंड्स के साथ चलने का दबाव रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फैंस उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उन पर ये दबाव इसलिए भी रहता है कि क्योंकि ब्यूटी ट्रेंड्स रातों-रात बदल जाते हैं। हालांकि अनन्या पांडे के लिए, आज खूबसूरती का मतलब ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं, बल्कि अपनी असलियत को अपनाना है। बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया कि वह कभी भी ब्यूटी ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागतीं, बल्कि वही चीजें अपनाती हैं, जो उन्हें स्वाभाविक रूप से पसंद आती हैं।

'कॉल मी बे' की एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं ट्रेंड्स को फॉलो वालों में से नहीं हूं। मुझे असल में ऑनलाइन सर्च करना पड़ता है कि अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा। मुझे बस इतना पता है कि मेरे लिए क्या सही है।'

अनन्या को फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' और 'चांद मेरा दिल' जैसी हालिया फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिली, हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाईं। सफलता और असफलता दोनों का अनुभव कर चुकीं यह एक्ट्रेस बड़े पर्दे के जादू में पक्का यकीन रखती हैं। अनन्या पांडे कहती हैं 'मुझे लगता है कि सिनेमा हमेशा रहेगा। मुझे थिएटर में जाकर हर तरह की फिल्में देखना पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा मजा हर हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्में देखने में आता है। मेरे लिए, फिल्में देखना मेरे बड़े होने का एक अहम हिस्सा रहा है। मैं नई पीढ़ी को थिएटर जाकर फिल्में देखने और हमारे सिनेमा को जिंदा रखने के लिए प्रोत्साहित करूंगी।'

हिंदुस्तान में हास्य छिछोरा हो चुका है

शेखर सुमन इस वक्त अपने शो 'शेखर टुनाइट' को लेकर सुर्खियों में हैं, जो गर्दा उड़ा रहा है और काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें वह राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हैं। शेखर ने इंटरव्यू में निडरता, सरकार से सवाल पूछने, आज की कॉमेडी और स्टैंडअप कॉमेडियंस पर बात की।

आज जब सिस्टम या सरकार के खिलाफ बोलना आसान नहीं रहा, क्या शेखर को डर नहीं लगता? इस पर वह कहते हैं, 'हां, आज लोगों में बहुत डर हो गया है, पर आपको डरना क्यों चाहिए? आप कोई गुनाह थोड़ी कर रहे है? किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी भाषा सभ्य होनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री से चाहे जितने तीखे सवाल करें, मगर उनके पद की गरिमा बहुत जरूरी है। हम जब मोदी जी के बारे में बोलते हैं तो उनकी गरिमा का पूरा ध्यान रखते हैं, पर जहां वो गलत हैं, वहा उंगली भी दिखाएंगे क्योंकि हमने उन्हें चुना है। अब जो शीर्ष पर है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। हमें लोंगों से भी जबरदस्त प्रतिक्रिया भी मिली है।'

टीवी चैनल्स में ऐसा शो करने का दम नहीं

इस शो को लाने की चुनौतियों और 'मूवर्स ऐंड शेखर्स' के 14 साल के लंबे अंतराल के सवाल पर वह बताते हैं, 'हर चीज का एक वक्त होता है। जब समय आता है तो चीजें अपने आप हो जाती हैं। मैं बहुत चीजों में व्यस्त था। मैंने एक फिल्म अकेडमी खोली है। मेरे नाटक 'साहिर अमृता' के 125 शो किए। मेरी इस साल 4 फिल्में/सीरीज आ रही हैं। उनकी शूटिंग थीं तो यह शो आगे-पीछे हो रहा था, पर हमारे सुपुत्र अध्ययन ने कहा लोगों का बहुत प्रेशर है और अब इसे करना ही है। तब मैंने कहा कि पहले तो इसकी परिभाषा बदली जाए कि यह कॉमेडी शो नहीं है।'

मेरे लिए 'शेखर टुनाइट' यह शो से परे है

'मेरे लिए यह एक तरह से इंकलाब है। यह एक लम्हा है जो मैं अपनी ऑडियंस के साथ गुजारता हूं। उनके साथ देश की सामाजिक-राजनीतिक बातें करता हूं। मेरे लिए यह शो से परे है। चुनौती ये थी कि इसे लाया किस प्लेटफॉर्म पर जाए क्योंकि किसी चैनल में इतना दम नहीं है कि ऐसा शो कर सके। वहां सब कायर बैठे हैं। उनका ज्ञान जीरो है। ओटीटी में भी अब वही चलन आ रहा है कि यह मत कहिए, वो मत कहिए तो मैं ऐसे बेवकूफों के आधीन काम नहीं कर सकता। इसलिए हमने यूट्यूब को चुना, जहां पूरी आज़ादी के साथ बोल सकें।'

वहीं, मौजूदा टीवी और स्टैंडअप कॉमेडी को लेकर उनका कहना है, 'मैंने खुद को और अपने शो को हास्य से बहुत दूर रखा है। मैं पहले जब कॉमेडी शो जज भी करता था तो लोग कहते थे कि आप हंसते क्यों नहीं? मैंने कहा कि आप बेवकूफी कर रहे हैं तो मुझे हंसी नहीं आ रही है। मैं हास्य से बहुत दूर हूं क्योंकि हिंदुस्तान में हास्य बहुत ही छिछोरा हो चुका है। वह अब बस लड़का लड़की बनकर, एक्टरों की नकल करके होता है। हास्य की गरिमा ही खत्म हो गई।

अध्ययन अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा

शेखर के शो के क्रिएटर और डायरेक्टर उनके बेटे अध्ययन सुमन हैं, जिनके लिए कभी शेखर ने फिल्म 'हार्टलेस' डायरेक्ट और प्रड्यूस की थी। बकौल शेखर, 'एक पिता के तौर पर यह बहुत गर्व और खुशी की बात है। मेरे लिए यह बहुत ही खूबसूरत साझेदारी है। जिस तरह उसने मुझे शो के प्रोमो में पेश किया वो बहुत ही क्लासी था।'

अध्ययन 19 की उम्र में मैच्योर नहीं था

'वह 19 साल की उम्र में बहुत बड़ा सितारा बन जाता तो शायद भटक जाता। तब उनमें वह मैच्योरिटी नहीं थी लेकिन तकलीफ, निराशा, असफलता आपकी जिंदगी को और पुख्ता बनाता है, तो अब वो जो इंसान बना है, उसकी समझ इतनी खूबसूरत हो गई कि वो जो काम करता है, वो बहुत कमाल करता है। यहां से वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसे रोकने के लिए दुनिया में प्रलय होना जरूरी है, तो हम सबके लिए यह बड़ी खुशी की बात है। पहले मैं कभी फिक्रमंद होता था कि वह नहीं कर पा रहा। मैंने फिल्म भी बनाई तो मेरी पत्नी ने अभी बड़े प्यार से मेरा गाल सहलाया और कहा कि देखो, मेरे बेटे ने तुम्हारा सारा कर्ज उतार दिया।'

स्वत्वाधिकार प्रकाशन एवं मुद्रक राजकुमार आमेटा के लिए स्मार्ट कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिन्टर्स, कोर्ट के सामने, माण्डलगढ़ से प्रकाशित एवं मुद्रित। मो. 9649222850 Email.smarthalchalnews@gmail.com